दैनिक
साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -190 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, गुरूवार, 2 जुलाई, 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

न्यूज ब्रीफ

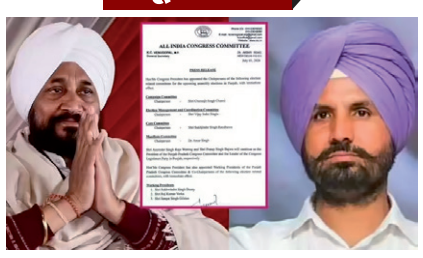

चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, चुनाव-संबंधी कमेटियों में कौन?

चंडीगढ़, एजेंसी | पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अगले साल होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव जीतने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनाव-संबंधी कमेटियों के लिए चेयरपर्सन और मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे।

कांग्रेस आलाकमान की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, चुनाव प्रबंधन और समन्वय कमेटी की जिम्मेदारी विजय इंदर सिंगला संभालेंगे। पार्टी ने उन्हें कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। वहीं चुनाव की कोर कमेटी का चेयरपर्सन सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया है, जबकि घोषणापत्र कमेटी की जिम्मेदारी अमर सिंह को सौंपी गई है। उन्हें घोषणापत्र कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है।

इसके अलावा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहेंगे।

फ्रांस दौरे पर निर्मला सीतारमण, निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी | केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को फ्रांस के आधिकारिक दौरे की शुरुआत की. इस दौरान वह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने तथा निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगी. इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम फ्रांस के ऐक्स-एन-प्रोवेंस में आयोजित होने वाला भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (ईएफडी) होगा. इस बैठक की सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक ऊर्जा और डिजिटल संप्रभुता मंत्री रोलैंड लेस्क्योर करेंगे. इस संवाद में दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों की तलाश करेंगे और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. फ्रांस प्रवास के दौरान वित्त मंत्री कई वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगी. इसके अलावा वह शीर्ष उद्योगपतियों के साथ एक गोलमेज चर्चा (राउंडटेबल) में भी हिस्सा लेंगी. इन बैठकों में भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार, बढ़ते निवेश अवसरों और दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. निर्मला सीतारमण 'नई मध्यम वर्गीय आबादी के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए' विषय पर आयोजित एक विशेष पैनल चर्चा में भी भाग लेंगी.

धान की फसल पर भी देंगे भावांतर योजना का लाभ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

• भोपाल प्रतिनिधि

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे हलधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर है। वे अपने अथक परिश्रम से पूरे समाज का उदर-पोषण करते हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प हैं क्योंकि किसान समृद्ध होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। शेर की दहाड़ और सतपुड़ा के पहाड़ और अब यहां की छत्रिय धान इस क्षेत्र की बड़ी पहचान है। छत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक टैग (जीआई टैग) मिल गया है। यह हमारी देशज और पारंपरिक कृषि का वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना (मनरेगा का नया स्वरूप) के तहत प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कार्यम लगातार चलायें जाएंगे। किसानों और रोजगार के जरूरतमंदों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदेश के 3 हजार 941 किसानों को 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से कोदो-कुटकी के बोनस के रूप में 2 करोड़ 84 लाख रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार श्रीअन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी दे रही है। हमने प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश के 16 हजार 754 से अधिक श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही 494 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से 629 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर सिवनी जिले को बड़ी सौगात दी। इसमें 349.33 करोड़ रुपये की लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.83 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल हैं।

मोदी केबिनेट ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी, बड़ी संख्या में पैदा होंगी नौकरियां

नई दिल्ली, एजेंसी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। फैसलों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को देते हुए बताया कि सरकार ने देश में आधुनिक और तेज रफ्तार सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क, यातायात व्यवस्था, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 8.1 किलोमीटर लंबी इस छह लेन सुरंग परियोजना पर कुल 6969.67 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह परियोजना संकर वार्षिकी प्रणाली यानि Hybrid Annuity Mode के अंतर्गत विकसित की जायेगी।

यूपी के मजदूरों को बड़ी सौगात! VB-GRAM-G एक्ट लागू, अब 125 दिन की गारंटी और रोज मिलेंगे न्यूनतम 300 रुपये

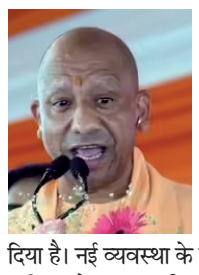

लखनऊ, एजेंसी | उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAM-G) योजना को लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को पहले के मुकाबले अधिक रोजगार, बढ़ी हुई मजदूरी और वैज्ञानिक तरीके से तैयार विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। करीब दो दशक तक ग्रामीण रोजगार का प्रमुख आधार रहे मनरेगा की जगह अब VB-GRAM-G योजना लागू हो गई है। नई योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाना भी है।

नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े ग्रामीण आबादी वाले राज्य में इस बदलाव का सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिलने की उम्मीद है।

अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन उठाने वाली रणनीति को दी मंजूरी, शुभेन्दु अधिकारी ने घुसपैठियों का दाना पानी बंद किया

• कोलकाता, एजेंसी

कोलकाता | घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। देश में अवैध घुसपैठ और बदलती जनसंख्या संरचना पर केंद्र सरकार पूरी तरह आक्रामक मोड़ में आ चुकी है। जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपनी पूरी रणनीति बता दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने घुसपैठियों का दाना पानी बंद करने की दिशा में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है।

लाखों संदिग्ध लाभार्थियों के नाम सरकारी योजनाओं से हटाए जा चुके हैं और नागरिकता की कड़ी जांच शुरू हो चुकी है।

केंद्र सरकार अब साफ संकेत दे चुकी है कि अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की हर कोशिश पर निर्णायक प्रहार होगा।

हम आपको बता दें कि जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। समिति ने साफ कर दिया है कि वह देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर जमीनी सच्चाई का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगी, ताकि अवैध घुसपैठ, संदिग्ध नागरिकता और जनसंख्या असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकें।

अगर अंडे फेंके तो..., महुआ मोइत्रा ने पहले दी चेतावनी, फिर भी हुईं 'एग ट्रीटमेंट' की शिकार

कोलकाता, एजेंसी | पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने पर 13 जून को चेतावनी देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उन पर अंडे फेंके जाते हैं, तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार से अंडे फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगाने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद टीएमसी सांसद अंडे का शिकार बन गईं। हंगामा करने वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए चोर-चोर की नारेबाजी भी की। महुआ मोइत्रा ने खुद फेसबुक लाइव के जरिए इस घटना के बारे

में बताया।

खबर है कि कालीगंज (नादिया जिला) के पलाशीपाड़ा में विधायक अलीफा अहमद के घर पर तृणमूल की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें महुआ शामिल हो रही थीं। उसी समय, प्रदर्शनकारी घर के बाहर जमा हो गए और काले झंडे लहराते हुए वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इसके बाद उन पर अंडे फेंके गए और चोर-चोर के नारे लगाए गए।

महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी सभी BJP कार्यकर्ता थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कहा कि देखिए, राज्य में सरकार बदलने के बाद से कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है।

पवन सिंह और निशांत कुमार ने ली एमएलसी पद की शपथ, पहली बार सदन पहुंचे बिहार विधान परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य

पटना | भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेकर औपचारिक रूप से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की।

पटना स्थित बिहार विधान मंडल परिसर में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित 10 विधान परिषद सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जनता दल (यूनाइटेड) के ललन प्रसाद से हुई। इसके बाद भाजपा के अनिल ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। चौथे क्रम पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि उनके बाद पांचवें क्रम पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शपथ ली। निशांत कुमार और पवन सिंह दोनों पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं।

मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए जारी किया 'रेड अलर्ट', माया नगरी की थमने लगी रफ्तार, लोकल और सड़कों का बुरा हाल

• मुंबई, एजेंसी

मुंबई | सपनों की नगरी मुंबई एक बार फिर मूसलाधार बारिश (Mumbai Rains) के आगे बेबस नजर आ रही है। शहर और उसके उपनगरों में मंगलवार रात से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी कर दिया है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार सुबह 8 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई के कई हिस्सों में 100 mm से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण निचले इलाकों और सबवे में गंभीर जलजमाव हो गया है। IMD ने मुंबई सहित पड़ोसी जिलों ठाणे और पालघर के लिए 'रेड अलर्ट' जारी करते हुए नागरिकों को बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।

नगर निकाय के ऑटोमैटिक रेन गेज) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 170.4 mm बारिश पूर्वी उपनगर के मानखुर्द इलाके में दर्ज की गई।

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं चरमरा गई हैं। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की सबअर्बन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाली हार्बर लाइन पर सुबह 4:52 बजे से 5:45 बजे के बीच ओवरहेड तार टूट गया। इसके कारण तड़के दफ्तर और काम पर निकलने वाले हजारों यात्री स्टेशनों पर फंस गए।

ऑपरेशन टाइगर से तंग आदित्य ठाकरे के ऐलान ने किया दंग, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे 2029 लोक सभा चुनाव

• मुंबई, एजेंसी

मुंबई | ऑपरेशन टाइगर का शिकार होने के बाद शिवसेना यूबीटी अब राजनीतिक बेचैनी के दौर से गुजर रही है। पार्टी के युवा नेता और वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अगला चुनाव फिर वर्ली से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, 'अगर आप कहेंगे तो मैं वाराणसी से लड़ूंगा।' इस एक वाक्य ने साफ संकेत दे दिया कि आदित्य ठाकरे भविष्य में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से ताल ठोंकने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक आत्मविश्वास है या फिर अनुभवहीनता से उपजा एक बचकाना दांव?

दरअसल वाराणसी कोई सामान्य लोकसभा सीट नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गढ़ बन चुकी है। 2014 से लेकर 2024 तक के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मोदी ने यहां केवल चुनाव नहीं जीते बल्कि विपक्ष को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी पराजित किया है। 2014 में मोदी ने अरविंद केजरीवाल को भारी अंतर से हराया था। 2019 में उनकी जीत का अंतर और बढ़ गया था। 2024 में भी विपक्षी गठबंधन तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी के प्रभाव को तोड़ नहीं पाया। वाराणसी में भाजपा ने केवल संगठन नहीं खड़ा किया बल्कि वहां मोदी की छवि को विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया है।

गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम परियोजना तक, मोदी ने वाराणसी को अपनी राजनीतिक पहचान का केंद्र बना दिया है।

टीवीके एमएलए का सनसनीखेज खुलासा : विजय सरकार गिराने के लिए 35 करोड़ का आफर, पुलिस जांच में बड़े नाम

नई दिल्ली, एजेंसी | सत्ता में सिर्फ़ दो महीने रहने के बाद, तमिलनाडु में विजय की सरकार को गिराने की एक कथित साज़िश का पता चला है। बुधवार को तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी के साथ यह मामला सामने आया। आरोप है कि DMK नेताओं ने TVK विधायकों को विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। यह साज़िश तब सामने आई जब 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के विधायक एन. एलैयाराजा ने आरोप लगाया कि उन्हें स्पीकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। इसके बाद पुलिस की जाँच का दायरा बढ़ गया है और जाँच के दौरान डीएमके के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी. अशोक कुमार के नाम भी सामने आए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब इलायराजा ने 29 जून को चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के अनुसार, थिरुनावुक्कारासु नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि वह 'इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज़' (IPDS) नाम की एक ओपिनियन पोलिंग संस्था का प्रमुख है। उसने कथित तौर पर विधायक से कहा कि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों की ओर से बात कर रहा है।

अपने आपको बरकोटी सरपंच बताने वाला जुआ सरगना अंकुश चौहान को पुलिस ने भेजा जेल

• सागर, प्रतिनिधि

सुरखी - थाना पुलिस ने एक ऐंसें जुआ फड संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जो अपने आपको बरकोटी कलां का सरपंच बताकर लग्जरी गाडियों से घूमकर रौब दिखाता फिरता था, और अपनी गाडी की नंबर प्लेट के ऊपर सरपंच लिखा रखता था,जिसका नाम अंकुश उर्फ प्रताप चौहान पिता दीवान सिंह चौहान निवासी बरकोटी बताया गया है, पुलिस के अनुसार अंकुश एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ सुरखी थाना में जुआ के 6 मामले अपराध क्रमांक 251/16, 348/19, 20/25,341/24,169/19,और जून 2026 ,एवं गौरझामर थाना में सट्टे का मामला 266/12 , गढाकोटा थाना 251/16 एवं मोटर व्हीकल एक्ट सहित थाना मोतीनगर सागर में अपराध क्रमांक 255/16 एवं थाना रहली सहित सागर जिले के अन्य थानों में मामले दर्ज हैं , पुलिस के अनुसार यह बेहद शातिर और आदतन अपराधी है जो स्वयं तो जुआ सट्टा खेलने का आदी हैं ही,

साथ साथ यह जहां तहां जुडा फड भी संचालित करता रहता है इसी कडी में बीते सप्ताह सुरखी थाना पुलिस ने अगरा गोंसरा के आसपास गौशाला के पीछे इसके द्वारा संचालित किये जा रहे जुआ फड पर कार्यवाही करते हुये मौके से नौ जुआरियों को पकडते हुये 71000 रुपये दो कारें और 9 मोबाइल जब्त किये थे जहां से जुआ फड का संचालक अंकुश चौहान फरार हो गया था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी,इसी दौरान 29 जून सोमवार की रात को सुरखी पुलिस को एक बार फिर अंकुश चौहान की आपराधिक गतिविधि करने की जानकारी मिली जिस पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुये न्यायालय में पेश किया जहां से उसे सागर केन्द्रीय जेल भेज दिया गया

पत्नी की जगह स्वयं संभालता है सरपंची, और, हास्पिटल में है वार्ड ब्वाय

यह अपनी चार पहिया गाडी की नंबर प्लेट पर सरपंच लिखे रहता और और ठाठबाट एकदम हाई प्रोफाइल लोगों की तरह रखता है, लेकिन वास्तव निर्वाचित सरपंच इसकी पत्नी सौली चौहान है, यह और इसका परिवार मूल रुप से भिंड के रहने वाले हैं इसके पिता स्वर्गीय दीवान सिंह चौहान बरकोटी कलां के शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र में कंपाउंडर थे जिनका लगभग दो साल पहले निधन को जाने के उपरांत, अंकुश चौहान की चतुर्थ श्रेणी में वार्ड ब्वाय के रुप में अनुकंपा नियुक्ति हो गई जो जिला चिकित्सालय और उसके बाद बरकोटी उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ हो गया

लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दिन रात जुआ सट्टा खेलने खिलाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नौकरी करने का समय कब मिलता होगा क्या वह कभी नौकरी करता होगा और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले शासकीय कर्मचारी पर क्या विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की या इस पर विभाग की कहीं कोई नजर ही नहीं है,

शाहगढ़ के पत्रकार नितिन जैन का शव बरमान के जंगल में फंदे से लटका मिला, मौत संदिग्ध

BMO डॉ. पूजा परमार के थे पति, बड़े खुलासे की चर्चा के बीच हत्या की आशंका, SDOP बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा*

• सागर, प्रतिनिधि

शाहगढ़/सागर | नगर के निर्भीक पत्रकार नितिन जैन का शव बुधवार को बरमान के जंगलों में पेड़ से लटका मिला। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पत्रकार जगत में शोक की लहर है।

जंगल में संदिग्ध हालत में मिला शव

सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।

BMO के पति थे नितिन जैन

मृतक नितिन जैन देवरी की नवागत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. पूजा परमार के पति थे। रसूखदार परिवार से जुड़े होने के कारण मामला और संवेदनशील हो गया है।

हत्या या आत्महत्या? गहराया रहस्य

मौत की परिस्थितियां पूरी तरह संदिग्ध हैं। परिजन और पत्रकार साथी इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नितिन निडर पत्रकार थे और कई संवेदनशील मामलों पर काम कर रहे थे।

बड़े खुलासे की थी तैयारी

सूत्रों के अनुसार नितिन जैन के पास किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा संदिग्ध वीडियो था। वे जल्द ही इस पर बड़ा खुलासा करने वाले थे। इसी बात ने मामले को और पेचीदा बना दिया है।

पुलिस का बयान

SDOP नरसिंहपुर अभिनव मिश्रा ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत दम घुटने से हुई या फांसी पर लटकाने से पहले कुछ और हुआ। फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है।

परिजनों और पत्रकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। घटना के बाद शाहगढ़-देवरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर अवैध बीज भण्डारण पर एफआईआर दर्ज

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर आलोक ट्रेडर्स प्रो श्री आलोक जैन जरूआखेडा में सोयाबीन बीज का अवैध एवं नकली भंडारण एवं पैकिंग करते हुए पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।

• सागर, प्रतिनिधिसागर | कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 29/06/2026 को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमन मिश्रा , उप संचालक कृषि श्री राजेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन मैं अवैध बीज विक्रय की रोकथाम हेतु जु रू आ खे ड़ा मै अवैध सोयाबीन बीज के व्यापार की जानकारी प्राप्त हुई थी । जिस पर आलोक ट्रेडर्स जरूवाखेड़ा की गोदाम में औचिक निरीक्षण किया गया। गोदाम में 40 किलो ग्राम की पैकिंग में 29 बैग सोयाबीन मशीन द्वारा पैक अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल ललितपुर की बोरी में पाया गया एवं अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल की नवीन 116 खाली बोरी गोदाम स्थल पर पाई गई । लगभग 100 जूट के बोरे 50 किग्रा के सोयाबीन का कच्चा माल पाया गया। जिस पर बीज गुण नियंत्रण आदेश के तहत करवाईं की गई।

अन्नपुर्णा ब्रांड अन्नपूर्णा दल मिल के नाम का दुरूपयोग

अवैध बीज की मशीन से सील पैकिंग बोरी अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल ललितपुर लिखी हुई बोरी गोदाम में पाई गई। बोरी पर दर्ज मोबाइल नबंर पर फोन लगाने पर वह मोबाइल नंबर श्री अमित जैन ललितपुर का होना पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अन्नपुर्णा दाल मिल प्रतिष्ठान का व्यापार विगत 5 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया है। संबंधित द्वारा प्रतिष्ठान के नाम एवं मोबाइल नबंर का दुरूपयोग किया गया है जिस पर कठोरतम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उक्त कार्रवाई के दौरान श्री एम के प्रजापति परियोजना संचालक आत्मा, श्री अनिल राय अनुविभागीय अधिकारी कृषि, श्री अंकित रावत सहायक संचालक कृषि, श्री जे. एल. विश्वकर्मा, श्री भूपेंद्र राजपूत तकनीकी सहायक एम सागर उपस्थित रहे।

जल संरक्षण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 2026

» कार्यक्रम के मुख्यातिथि राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया » जनप्रतिनिधियों ने अभियान के कार्यों की प्रदर्शनी एवं प्राचीन बावड़ी का भी अवलोकन किया » उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारी-कर्मचारी एव संस्थाओं के नागरिक हुए सम्मानित*

• सागर, प्रतिनिधि

छतरपुर | जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के उद्देश्य से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 का जिला स्तरीय समापन समारोह मंगलवार को नगरपालिका परिषद छतरपुर शहर के अंतर्गत स्थित मोटे के महावीर मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं गंगा पूजन के साथ किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार सहित छतरपुर विधायक ललिता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, नपा उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी उपस्थित रहे एवं जिला कलेक्टर पार्थ जैसवाल, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, सीएमओ माधुरी शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 19 मार्च से प्रारंभ हुआ यह अभियान लगभग 4 माह तक चला। जिसमें अनेक जल संरचनाओं के संवर्धन के कार्य किए गए। जिसमें शहर में विंध्यवासिनी तलैया, मोटे के महावीर की बावड़ी, सांतरी तलैया एवं ग्लावमगरा तालाब सहित अनेक कार्य इस अभियान में किए गए।

राज्यमंत्री ने अभियान में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से जल बचाने का आव्हान किया। साथ ही लोगो से अपने क्षेत्र की प्राचीन बावड़ी व तालाबों को संरक्षित करने के लिए अभियान में शामिल करने की बात कही।

छतरपुर विधायक श्रीमती यादव ने कहा कि पुराने तालबों, बावड़ीयों एवं धरोहरों को सहेजने के लिए जनसहयोग जरूरी है। इसका अस्तित्व बना रहे इसके लिए अभियान का संचालन किया गया। साथ ही उन्होंने बरसात के दृष्टिगत लोगों से नदी नालों में जल भराव की स्थिति न बने इसके लिए सीमांकन कराए जाने एवं लोगों से अतिक्रमण न करने की बात कही।

इस दौरान अभियान के अंतर्गत जिले में किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, वहीं उपस्थित लोगों ने लोकगीतों के माध्यम से जल बचाने का संदेश सुना। अतिथियों ने अभियान से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा मंदिर परिसर में बनी प्राचीन बावड़ी का निरीक्षण कर किए गए कार्य का अवलोकन किया और संरक्षण कार्यों की सराहना की।

समापन समारोह में अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, विभिन्न विभागों, अधिकारियों-कर्मचारियों, श्रमदान करने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जलदूतों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवा संगठनों, किसानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित जल संरक्षण में सहयोग करने वाले अनेक संस्थानों को सम्मानित किया गया। एवं कार्यक्रम में जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने और भविष्य में भी जल स्रोतों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 मध्य प्रदेश में जल संरक्षण बना जन-जन का अभियान- राज्यमंत्री श्री लोधी जल संरक्षण को जीवन पद्धति बनाना होगा- पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉ. कुसमरिया सिंचाई परियोजनाओं से बदली दमोह की तस्वीर, किसानों की आय बढ़ी- विधायक श्री मलैया

प्रदेशभर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूर्ण, 10,514 करोड़ रुपये की लागत से जल संसाधनों के संरक्षण को मिली नई गति दमोह स्थित बेलाताल में हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन

• सागर, प्रतिनिधि

दमोह | मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के अंतर्गत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को केवल शासकीय कार्यक्रम तक सीमित न रखकर समाज का संस्कार बनाना है, प्रदेश प्राकृतिक जल स्रोतों से समृद्ध है, लेकिन बदलते जलवायु चक्र, भूजल के अत्यधिक दोहन तथा जल प्रबंधन के प्रति बढ़ती असावधानी को देखते हुए जल संरक्षण आज सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। इसी दृष्टि से आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है, इस आशय के विचार प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर बेलाताल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में व्यक्त किये।

राज्यमंत्री श्री लोधी ने कहा जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के अंतर्गत प्रदेशभर में लगभग 3 लाख 62 हजार जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। इन कार्यों पर लगभग 10,514 करोड़ रुपये की लागत आई है, अभियान के तहत हजारों खेत तालाब, भू-जल रिचार्ज संरचनाएं, अमृत सरोवर, चेक डैम, जलाशयों का जीर्णोद्धार, नालों की सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जल संरक्षण संबंधी जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की गई हैं। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, उन्होने कहा प्रदेश सरकार का उद्देश्य जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल संसाधनों का निर्माण करना तथा सतत विकास की दिशा में मजबूत आधार तैयार करना है।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा जब तक जल संरक्षण को हम अपनी जीवन पद्धति में आत्मसात नहीं करेंगे और अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक जल संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है, उन्होंने कहा पूर्व समय में खेत-तालाब, रामताल एवं अन्य पारंपरिक जल स्रोत जल संरक्षण के प्रभावी माध्यम थे। वर्तमान में शासन द्वारा अमृत सरोवर जैसी योजनाओं के माध्यम से जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।

दमोह विधायक जयंत मलैया ने कहा आज दमोह जिला पानी से लबालब है और सिंचाई परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम किसानों के जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सीतानगर, पंचमनगर और सतधरू जैसी सिंचाई परियोजनाओं के कारण क्षेत्र में खेती की तस्वीर बदल गई है, उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि भूमि के मूल्य में लगभग पाँच गुना तक वृद्धि हुई है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलने से किसान अब वर्ष में तीन फसलें ले रहे हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस अभियान को प्रारंभ कराया। हमें गर्व है कि जिले में अभियान के तहत बहुत ही अच्छा काम हुआ सभी संस्थाओं, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया और जलस्रोतों के पुनर्जीवन के लिए कार्य किया।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. मंजू धर्मेंद्र कटारे ने कहा जब तक सभी लोग एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए हम सभी को अपनी सोच बदलकर दूसरों को सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह प्रवीण फुलपगारे ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से शुरू हुआ था और 30 जून को समाप्त करना था, कार्यक्रम के तहत जलस्रोतों को सुरक्षित करने में लोगो की जागरूकता और सहभागिता बनानी थी और जन जागरूकता फैलानी थी, मुझे बताते हुए यह खुशी है की जल संवर्धन की रैंकिंग में हमारा दमोह जिला 17 वे नंबर पर है।

इस अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वालो का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएँ, शिक्षक और अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान जल संवर्धन-संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे और आभार सुशील नामदेव ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक जयंत मलैया, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, उपाध्यक्ष मंजू धर्मेन्द्र कटारे, गोपाल पटेल, अमित जैन (गोलू बजाज), रामेश्वर चौधरी, संजय यादव, राघवेन्द्र सिंह परिहार, कविता राय, संतोष रोहित सहित अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक, सम्मानीय मीडियाजन, अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

जनजातीय छात्रावासों के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति बढ़ी

भोपाल । मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए सतत?निर्णय ले रही है। इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले छात्र/छात्राओं की शिष्यवृत्ति की दरों को प्रत्येक वर्ष माह मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित कर माह जुलाई में छात्रावास / आश्रम प्रारंभ होने से प्रभावशील होगी। जारी आदेश के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2026-27 के लिए शिष्यवृत्ति की नई दरें निर्धारित की गई हैं। अब छात्रावास एवं आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1,720 रुपये प्रतिमाह तथा बालिका विद्यार्थियों को 1,770 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाएगी।

बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 31 अक्टूबर तक

भोपाल। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। योजना के अंतर्गत बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत संतानों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने तथा समय-सीमा में आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर एक जून से प्रारंभ हो चुके हैं। पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने महाविद्यालयों से अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने और उनके आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है।

योजना के अंतर्गत कक्षा एक से लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा एक से चौथी तक के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये, कक्षा 5 से 8 तक 1,500 रुपये, कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को 2,000 रुपये, कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये तथा आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। योजना का लाभ बीड़ी श्रमिकों, लौह अयस्क, मैंगनीज एवं क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खदान श्रमिकों के पात्र बच्चों को दिया जाता है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माना वसूला

भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। सोमवार को निगम के अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 74 मामलों में कुल 12,800 रुपये का स्पॉट फाइन और जुर्माना वसूला।

नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर जोन-13 में 23 मामलों में 4,500 रुपये, जोन-14 में 29 मामलों में 2,900 रुपये, जोन-15 में 20 मामलों में 3,300 रुपये तथा जोन-16 में दो मामलों में 2,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और खुले में सी एंड डी वेस्ट फेंकने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए इस प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण तोड़े, मेट्रो परियोजना में बाधक झुग्गियां हटाईं

भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सोमवार को व्यापक अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर कार्रवाई की। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध कब्जे हटाए, नाले पर बने अवैध पिलर और छज्जों को ध्वस्त किया तथा यातायात में बाधा बन रहे वाहनों और अन्य सामान को जब्त किया। अभियान के दौरान भारत माता चौराहा, नीलबड़, राहुल नगर, जवाहर चौक, सरस्वती नगर, लिंक रोड, अशोका गार्डन, हमीदिया रोड, शाहजहानाबाद, कोहेफिजा और लालघाटी सहित कई क्षेत्रों में ठेले, गुमटियां, पान पार्लर, फुटपाथ पर लगी दुकानें और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाया गया। साथ ही 50 आवागमन में बाधक चार पहिया वाहनों को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम अमले ने नौ ठेले, दो चार पहिया वाहन, 14 कुर्सियां और तीन टेबल जब्त किए।

भवन अनुज्ञा शाखा के सहयोग से नीलबड़ क्षेत्र में विद्या विहार स्कूल के सामने आठ दुकानों के बाहर नाले पर बने अवैध पक्के पिलर और छज्जों को पोकलेन मशीन से तोड़ा गया। वहीं जिला प्रशासन के साथ मिलकर गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मेट्रो परियोजना में बाधक सात झुग्गियां, दो टपरे और पांच ठेले हटाए गए। इसके अलावा भोपाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जवाहर चौक स्थित सरस्वती नगर में पांच मकान खाली कराकर जेसीबी से ध्वस्त किए गए। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

तकनीकी सुरागो से आगे बढ़ रही गोली मारकर दंपति की हत्या के मामले की जांच

भोपाल। शहर के ऐशबाग थाना इलाक में स्थित सुदामा नगर में रिटायर्ड दंपती हेमंत बारीक (70) और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक (70) की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या के मामले की जॉच में फिलहाल पुलिस को अज्ञात आरोपियो के संबध में कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। जांच टीम फिलहाल मोबाइल की कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करने के साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का अनुमान है की दोहरे हत्याकांड को किसी करीबी ने अंजाम दिया है, इसके पीछे संपत्ति या पैसों का विवाद हो सकता है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें घटनास्थल के साथ ही आासपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी हैं। साथ ही मृतक दंपती के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई जा रही है, जिससे घटना से पहले संपर्क में आए लोगों की जानकारी मिल सके।

बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में उप मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण

प्राकृतिक खेती और गोवंश सुविधाओं का लिया जायजा

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का दौरा कर वहां संचालित की जा रही प्राकृतिक खेती और गौवंश के लिए विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौवंश वन्य विहार परिसर में पूर्णत: प्राकृतिक रूप से उगाई गईं हरी सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्रियों को भी देखा और उनकी गुणवत्ता की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने उपस्थित किसान भाइयों और आमजनों से कहा कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में प्राकृतिक खेती का एक बेहतरीन और आदर्श मॉडल विकसित किया गया है। यहाँ कम जगह पर मल्टी-लेयर खेती की जा रही है, जिसमें सबसे नीचे हल्दी, अदरक और प्याज जैसी फसलें हैं, तो वहीं ऊपर लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, भिंडी और बैगन जैसी हरी सब्जियां सफलतापूर्वक उगाई जा रही हैं।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि इस पूरी खेती में डीएपी और यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बिल्कुल शून्य है। यह पूरी तरह से विष-मुक्त खेती है। उन्होंने किसानों में फैली इस भ्रांति को दूर किया कि केवल रासायनिक खादों से ही ज्यादा उत्पादन संभव है। शुक्ल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न केवल फसलों का उत्पादन बेहतर होता है और आमदनी बढ़ती है, बल्कि इससे उत्पादित साग-सब्जियों के सेवन से हमारे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि इस गौवंश वन्य विहार में लगभग नौ हजार बेसहारा गायों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है, जिससे पर्याप्त मात्रा में गोबर और गोमूत्र उपलब्ध होता है। इसी का उपयोग कर यहाँ बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ गेहूं, धान, मूंग के साथ-साथ बड़े पैमाने पर बागवानी के तहत फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वे बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का दौरा करें और यहाँ आकर सीखें कि किस प्रकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से लागत को कम करके लाभदायक खेती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को अपनाकर हम न केवल अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचा सकते हैं, बल्कि रासायनिक खादों के आयात पर खर्च होने वाली देश की विदेशी मुद्रा की भी बड़ी बचत कर सकते हैं। अंत में उन्होंने पूरी लगन से इस कार्य में जुटे सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

टेंट व्यापारियों ने वृक्षारोपण किया

भोपाल

भोपाल टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रिंकू भटेजा ने बताया कि ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आव्हान पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को पूरे देश भर में वृक्षारोपण किया जाता है मध्यप्रदेश में फेडरेशन ऑफ़ एमपी टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह खनूजा के अनुरोध पर मध्य प्रदेश के हर जिले में वृक्षारोपण किया जाता है इसी के तहत भोपाल टेंट लाइट केटर्स एसोसिएशन के द्वारा हिंदी भवन पॉलिटेक्निक चौराहा में वृक्षारोपण किया गया। इस पुनीत और जनहितकारी कार्य में आज फेडरेशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह खनूजा, संयोजक कोर कमेटी रामबाबू शर्मा,कोषाध्यक्ष संजय जैन, भोपाल टेंट लाईट केटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वदेश सोनी, महासचिव योगेश श्रीवास्तव, प्रभात सोनी, विश्वबंधु सोनी, महेश यादव, कैलाश राठोर, विशाल शर्मा, सुनील शाह,डी.आर.सिंह, राजकुमार माहेश्वरी, संदीप शर्मा,तरुण चतुर्वेदी, यशपाल छावड़ा आदि सदस्यों की उपस्थिति रही।

एनसीटीई पाठ्यक्रमों के द्वितीय चरण का सीट आवंटन जारी

भोपाल । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत एनसीटीई पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब तक 99,597 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें से 78,784 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 21,242 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 19,166 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत 18,563 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रथम चरण में 16,856 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर अब तक कुल 35,419 विद्यार्थियों को एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट आवंटित की जा चुकी है। द्वितीय चरण में सीट आवंटित विद्यार्थियों को 29 जून से 4 जुलाई 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रवेश प्रक्रिया में अब तक स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 2 लाख तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 60 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अब तक लगभग 2 लाख 78 हजार विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने द्वितीय चरण में सीट आवंटित सभी विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुल्क जमा कर संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रवेश सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी पर परामर्श कार्यशाला आयोजित

भोपाल, नप्र। भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी' पर मध्य एवं पश्चिमी भारत क्षेत्र के लिए कंसल्टेशन वर्कशॉप (परामर्श कार्यशाला) का आयोजन भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. एम. मोहंती (निदेशक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान) ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए भारत में 'भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी' की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिट्टी के प्रकार, अलग-अलग तरह के मौसम, आदिवासी खेती, इकोसिस्टम से मिलने वाली सेवाओं और मुख्य फसलों/खेती के तरीकों जैसी विशेषताओं और चुनौतियों के कारण, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिए यह परामर्श कार्यशाला खास है; इसलिए, क्षेत्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की सेहत से जुड़ी नीति बनाने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में, डॉ. ए.के. नायक, उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), आईसीएआर, नई दिल्ली ने हमारे देश में 'भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी' शुरू करने की दिशा में दूरदर्शी लोगों की तारीफ़ की। उन्होंने पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग पैरामीटर्स और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी' को लागू करने के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस एक अहम दस्तावेज़ हैं और इनमें किसानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), इंडस्ट्री, अधिकारियों और वैज्ञानिकों जैसे स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी ज़रूरी है। उन्होंने कई मंत्रालयों द्वारा लागू की जा रही सरकारी योजनाओं के तालमेल की गुंजाइश पर ज़ोर दिया और डिजिटल टूल्स के ज़रिए उन्हें सॉइल हेल्थ पॉलिसी से जोड़ने का आग्रह किया। इस कार्यशाला में किसानों, वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों तथा निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए मध्य एवं पश्चिमी भारत क्षेत्र के लिए 'भारत मृदा स्वास्थ्य नीति' के प्रारूप तैयार करने हेतु अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए।

97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न, विद्युत ग्रिड को और मजबूत बनाने पर जोर

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोमवार को भोपाल में 97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी (ओसीसी) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य विद्युत ग्रिड के सुरक्षित, विश्वसनीय एवं समन्वित संचालन, विद्युत मांग-आपूर्ति प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण, ग्रिड अनुशासन, ट्रांसमिशन समन्वय तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही परिचालन संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझावों एवं निर्णयों पर सहमति बनी, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता प्रदीप सचान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकी) सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी, प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, अडाणी पावर, रेलवे तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की कार्यवाही का संचालन ओसीसी के सदस्य सचिव विवेक कुमार अग्रवाल ने किया।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ग्रिड स्थिरता बनाए रखने, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग तथा सभी विद्युत उपक्रमों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थाओं को मिलकर कार्य करना होगा। बैठक के सफल आयोजन पर सहभागी संस्थाओं ने कंपनी की व्यवस्थाओं और समन्वय की सराहना भी की।

कोलकाता में होगी विधानसभा समितियों की अंतिम समीक्षा बैठक, अध्यक्षता करेंगे नरेन्द्र सिंह तोमर

भोपाल, नप्र। विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से गठित पीठासीन अधिकारियों की समीक्षा समिति की अंतिम बैठक 3 और 4 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा, कोलकाता में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे। लोकसभा द्वारा गठित इस समिति में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सहित छह राज्यों के विधानमंडलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पूर्व समिति की दो बैठकें भोपाल और जयपुर में आयोजित हो चुकी हैं। अंतिम बैठक में विभिन्न विधानसभा समितियों के कार्यों पर हुए विमर्श के आधार पर तैयार अनुशंसाएं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएंगी। बैठक के साथ ही श्री तोमर पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रशिक्षण शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। वे वहां विधायकों को प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और सदन में जनप्रतिनिधियों के आचरण जैसे महत्वपूर्ण संसदीय विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। प्रशिक्षण सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। यह आयोजन संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने और विधायकों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संभागायुक्त ने वर्षाकाल में सड़कों के बेहतर रख-रखाव और त्वरित मरम्मत के दिए निर्देश

भोपाल, नप्र। भोपाल संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को शहर की सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों की समीक्षा बैठक लेकर वर्षाकाल में सड़कों को दुरुस्त रखने और जलभराव की स्थिति नहीं बनने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एवं रख-रखाव से जुड़ी सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है।

बैठक में संभागायुक्त ने संत हिरदाराम नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान पीएनजी गैस आपूर्ति बाधित नहीं होने देने और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया। श्री शर्मा ने नगर निगम को बारिश के दौरान सड़क मरम्मत के लिए पूरी तैयारी रखने और शिकायत मिलने पर न्यूनतम समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भोपाल-सागर-कानपुर मार्ग सहित शहर के बाहरी मार्गों को बेहतर बनाए रखने, सड़क दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारने तथा आवश्यक स्थानों पर चेतावनी संकेतक लगाने को कहा।

इसके अलावा आगामी जीआईएस कार्यक्रम और सांची-भोजपुर जैसे पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने तथा मेट्रो निर्माण से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराना सभी एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जन्मदिवस पर गो-पूजन, वृक्षारोपण एवं विशाल धर्मसभा आयोजित

भोपाल, नप्र। आचार्य पंकज शर्मा के जन्मदिवस के पावन अवसर पर भोपाल दादाजी परिवार द्वारा डॉ. श्रीकांत अवस्थी के श्री कृष्णा फार्म हाउस में गो-पूजन, वृक्षारोपण एवं विशाल धर्मसभा का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया गया। श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दादाजी अष्टक एवं 501 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर राष्ट्र, समाज और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान डॉ. श्रीकांत अवस्थी के फार्म हाउस पर आचार्य पंकज शर्मा का जन्मोत्सव श्रद्धाभाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य पंकज शर्मा का शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मान किया गया तथा पूज्य दादाजी श्री बजरंग दास जी महाराज के श्रीचरणों में उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं लोककल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में श्री राम मानव शक्ति यज्ञ में निस्वार्थ सेवा देने वाली मातृशक्ति एवं कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। उन्हें श्रीराम दरबार एवं दादाजी भगवान के विग्रह भेंट कर उनके सेवाभाव का अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर डॉ. श्रीकांत अवस्थी, राकेश चतुर्वेदी, रामदास चौधरी, राजीव गुलाटी, मनोज साहू, ओमप्रकाश चौबे, विकास लोधी, अरुण द्विवेदी, कार्तिक शर्मा एवं गोपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दादाजी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के कॉन्सुल जनरल की शिष्टाचार भेंट

भोपाल, नप्र। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से सोमवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल में नीदरलैंड के मुंबई स्थित कॉन्सुल जनरल नबील ताउआती ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार और कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने मध्यप्रदेश पुलिस की आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी नवाचार, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण और नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली की जानकारी साझा की। उन्होंने राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री मकवाणा ने प्रदेश में संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए व्यापक जनभागीदारी के साथ अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में सामुदायिक पुलिसिंग, जनसुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। कॉन्सुल जनरल नबील ताउआती ने मध्यप्रदेश पुलिस के नवाचारों और जनहित में चलाए जा रहे अभियानों की सराहना करते हुए भविष्य में सहयोग एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की।

|| संपादकीय ||

क्या हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे?

वेनेज़ुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है, राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है, लेकिन एक प्रश्न बार-बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है-क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुनः उसी लापरवाह विकास-यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं, न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है, नदियां उफान पर आती हैं, पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े-बड़े दावे, ऊंची-ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि उसकी पूर्व तैयारी, संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं।

वेनेज़ुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प, 2001 का भुज भूकम्प, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2023 की जोशीमठ भू-धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है-प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता।

वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन, किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा, लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पूर्व, गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन, गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची-ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी?

किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है, जब अचानक बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके, तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक-दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है।

निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू-माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ-लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों, जलाशयों, नदी तटों और भू-संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था, तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा? क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए लाखों नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है? यह केवल कानूनी प्रश्न नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर विकास न्यासों तथा भवन निर्माण की अनुमति देने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल नक्शों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हो सकती। प्रत्येक निर्माण की तकनीकी, पर्यावरणीय और संरचनात्मक जांच अत्यंत कठोरता से की जानी चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व है।

एक अन्य गंभीर चिंता जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की है। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करना, जंगलों का अंधाधुंध विनाश, अतिक्रमण, खनन और अनियोजित शहरीकरण ने प्रकृति के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप भूस्खलन, अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार आने वाली त्रासदियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि विकास का मॉडल प्रकृति-विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति-संगत होना चाहिए। यह मान लेना भी खतरनाक है कि जिस क्षेत्र में पहले कभी बड़ा भूकम्प नहीं आया, वहां भविष्य में भी खतरा नहीं होगा। धरती के भीतर क्या हलचल चल रही है, इसका पूरा रहस्य आज भी मानव नहीं जान पाया है। इसलिए केवल पुराने अनुभवों के आधार पर किसी क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित मान लेना आत्मघाती हो सकता है। आज भवन निर्माण केवल भूकम्प को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता। अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, तेज हवाएं, तापमान में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों को भी नगर नियोजन का हिस्सा बनाना होगा। भविष्य के शहरों को बहुस्तरीय सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर विकसित करना समय की मांग है। आपदा आने के बाद राहत और पुनर्वास पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की अपेक्षा पहले से सुरक्षा पर निवेश करना कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण है। सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को भी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक होना होगा। विद्यालयों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। आधुनिक चेतावनी प्रणालियों को गांवों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाली तबाही को काफी हद तक कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक, कठोर निगरानी, पारदर्शी प्रशासन और जागरूक नागरिकों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। प्रकृति कभी यह नहीं पूछती कि इमारत कितनी महंगी है, किस बिल्डर ने बनाई है या वह किस शहर में खड़ी है।

भारत और सेशेल्स के बीच विकसित नए द्विपक्षीय सम्बन्धों के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

> सेशेल्स हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। इसलिए भारत के साथ इसकी बढ़ती साझेदारी से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

भारत और सेशेल्स के बीच हाल के वर्षों में विकसित हुए द्विपक्षीय संबंध केवल आर्थिक और सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके व्यापक अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सेशेल्स दौरे से इस बात को और भी बल मिला है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल द्विपक्षीय मैत्री का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, शक्ति-संतुलन, समुद्री व्यापार, जलवायु सहयोग और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण संबंध हैं।

यही नहीं भविष्य में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से इन संबंधों का अंतरराष्ट्रीय महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसलिए आइए इसके वैश्विक मायने को समझने और पाठकों को समझाने की एक विनम्र कोशिश करते हैं-

पहला, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूतः सेशेल्स हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। इसलिए भारत के साथ इसकी बढ़ती साझेदारी से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

दूसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलनः हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश और सामरिक विस्तार के बीच सेशेल्स के साथ भारत के मजबूत संबंध क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। इससे छोटे द्वीपीय देशों के पास विविध साझेदारों के साथ सहयोग के विकल्प भी बने रहते हैं।

तीसरा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोगः दोनों देशों के बीच समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ा है। इससे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सामूहिक समुद्री सुरक्षा को लाभ मिलता है।

चौथा, SAGAR नीति को मजबूतीः भारत की Security and Growth for All in the Region (SAGAR) नीति को सेशेल्स के साथ सहयोग से व्यावहारिक आधार मिलता है। यह नीति क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और साझा विकास पर बल देती है।

पांचवीं, ब्लू इकोनॉमी में सहयोगः सेशेल्स की अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों पर आधारित है। भारत समुद्री जैव संसाधन, मत्स्य पालन, समुद्री अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं।

छठा, जलवायु परिवर्तन पर साझेदारीः समुद्र-स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से छोटे द्वीपीय देशों को गंभीर खतरा है। भारत और सेशेल्स इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं और जलवायु न्याय तथा टिकाऊ विकास की वकालत करते हैं।

सातवां, हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीति में महत्वः - भारत का मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण सेशेल्स जैसे साझेदार देशों के सहयोग से अधिक प्रभावी बनता है। इससे क्षेत्र में स्थिरता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

आठवां, भारत की वैश्विक कूटनीति को बलः सेशेल्स जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की वैश्विक दक्षिण (Global South) में विश्वसनीय साझेदार की छवि को मजबूत करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल द्विपक्षीय मैत्री का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, शक्ति-संतुलन, समुद्री व्यापार, जलवायु सहयोग और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण संबंध हैं। भविष्य में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से इन संबंधों का अंतरराष्ट्रीय महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है।

- कमलेश पांडेय

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

समझौता संभव नहीं

आखिर राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान क्या चाहते हैं? वे युद्ध को समाप्त करने के पक्षधर हैं अथवा युद्धविराम का ढोंग करते रहना चाहते हैं? दुनिया की पतली आर्थिक स्थितियों और ऊर्जा-खाद्य संकट के कोहराम के लिए दोनों ही देश जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट लिखी है, जिसके भाषायी मायने साफ हैं कि उन्होंने मान लिया है कि ईरान मानने लायक नहीं है, लिहाजा अब सेना के जरिए काम पूरा करना पड़ेगा। यदि ऐसा करना पड़ा, तो ईरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। पलटबयान में ईरान भी कम नहीं है। उसके प्रवक्ता भी खूब धमकियां देते हैं। अप्रत्याशित हथियारों की बात करते हैं। समझौते के सहमति-पत्र पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दस्तखत किए थे। उसकी अपनी राष्ट्रीय और द्विपक्षीय महत्ता और गरिमा होती है, लेकिन ईरान में कट्टरपंथियों और आईआरजीसी का एक तबका ऐसा है, जो युद्ध खत्म करने के खिलाफ है। और कितना बर्बाद, खंडहर होना चाहता है ईरान? उसकी 40 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी-रेखा के तले जीने को विवश है। मुद्रास्फीति 65-70 फीसदी के करीब है, लिहाजा ब्रेड, मांस, खाने-पीने की आम चीजों की कीमतें 140 फीसदी तक उछल गई हैं। अर्थव्यवस्था में 8.8 से 10 फीसदी तक की गिरावट संभावित है। यह आकलन आईएमएफ का है। ईरानी मुद्रा 'रियाल' का ऐसा ऐतिहासिक पतन हुआ है, लिहाजा लोग किश्तों पर 'रोटी' खाने को विवश हैं। युद्ध में ईरान का नुकसान करीब 270 अरब डॉलर आंका गया है, जो उसकी जीडीपी के 57 फीसदी के बराबर है। और कितना दरिद्र होगा ईरान? ताजा हालात ये हैं कि अमरीकी सेना ने ईरान के 10 मिसाइल और ड्रोन के ठिकानों पर हमले किए। उसने ईरान के रडार और सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। पलटवार में ईरान ने कुवैत के अमरीकी वायुसेना बेस और बहरीन के अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े पर मिसाइल हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। ईरान ने कतर में भी हमले किए, लेकिन इस बार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नहीं छुआ। शायद कोई 'मोटी डील' हो गई होगी! अमरीका ने होर्मुज के तटीय इलाकों में, केश्म द्वीप और सिरिक में, एफ-16 समेत 6 लड़ाकू विमानों से हमले किए और ईरान के 4 अहम ठिकानों को तबाह, बर्बाद करने का दावा किया। अब ईरान ने हुंकार भरी है कि होर्मुज पर उसका ही कब्जा बरकरार रहेगा। जिस जहाज, टैंकर ने उसके निर्देश नहीं माने, तो उन पर हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।

यह समझौते और युद्धविराम की कौन-सी भाषा है? इन हमलों और जंगी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अमरीका-ईरान के दरमियान एक ठोस, स्थायी समझौता संभव नहीं है। दोनों की मानसिकता ही समझौते की नहीं है, बल्कि वे अब भी कट्टर दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दोनों के बीच जिस तरह हमले बोले जा रहे हैं, वे कोई सामान्य, छुटपुट टकराव नहीं हैं, संपूर्ण युद्ध के आक्रमण हैं। शायद इस युद्ध से अमरीकी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर उतना असर न पड़े, लेकिन युद्ध के दौरान उसके भी 14 सैनिक मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। यह पेंटागन की ही रपट है कि 42 मानवरहित विमान, ड्रोन, लड़ाकू विमान नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए। अमरीका का कुल युद्ध खर्च 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। पेंटागन ने शेष युद्ध और हथियारों के लिए 80 अरब डॉलर (करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए) के अतिरिक्त बजट की मांग संसद से की है, लेकिन संसद ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। यदि युद्ध के संदर्भ में भारत का आकलन करें, तो ईरान युद्ध से भारत को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापक आर्थिक और राजकोषीय झटका लगा है। भारत करीब 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल के दाम 110 डॉलर तक उछले थे, तो पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, सीएनजी, खाद आदि के दाम भी बढ़ाए गए थे। फिलहाल उन्हें सस्ता नहीं किया गया है।

टेक्नोलॉजी

अब फोन से ही कंट्रोल करें अपना AI एजेंट! OpenClaw ने पेश किया अपना नया मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है. वहीं, अब एआई ही नहीं बल्कि एआई ऐजेंट्स भी आ चुके हैं जो लोगों के ऑर्डर पर काम करते हैं. इसी कड़ी में ओपन-सोर्स AI असिस्टेंट OpenClaw ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट के बाद आप एआई ऐजेंट को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकेंगे. जी हां, दरअसल कंपनी ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए एक नया ऐप जारी किया है.

आपके लिए काम करेगा AI - बता दें कि OpenClaw की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ बातचीत तक लिमिटेड नहीं है. बल्कि ये आपके लिए काम भी करेगा. उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर आप इसे कैमरा, फोटो, अपने कॉनटेक्ट्स या लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति देते हैं तो ये आपके लिए वो सब करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं.

मीटिंग याद दिलाने से लेकर डिवाइस में फोटो मैनेज करने से लेकर ये सभी रोजमर्रा के काम आपके लिए आसानी से कर सकता है. इसी वजह से ये बाकी एआई ऐजेंट्स के मुकाबले काफी अलग है. इतना ही नहीं, ये एआई ऐजेंट आपको लोकेशन बताने से लेकर आपके लिए नया रास्ता खोजने तक के काम को भी कर सकता है. एआई ऐजेंट ने आज की दुनिया में लोगों के काम को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब ऐसे ऐप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं.

OpenClaw के काम करने का तरीका - आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenClaw नॉर्मल AI चैटबॉट्स से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. जहां एक तरफ नॉर्मल एआई डॉयरेक्ट कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होती हैं. वहीं, दूसरी तरफ OpenClaw एक Gateway के जरिए काम करता है. इसे AI असिस्टेंट का कंट्रोल सेंटर भी कहा जा सकता है.

बता दें कि ये Gateway यूजर के कंप्यूटर, किसी क्लाउड सर्वर या निजी सिस्टम पर आसानी से चलने में सक्षम है. कंपनी ने अब जो नया मोबाइल ऐप पेश किया है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा जिसकी मदद से आप एआई ऐजेंट से ऑर्डर देकर कुछ ही काम करवा सकते हैं.

जनरल नॉलेज

लोकसभा या राज्यसभा, किसके सांसदों के पास है ज्यादा पैसा? यहां देखें हिसाब-किताब

भारतीय संसद में कानून बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों की संपत्ति इन दिनों नए रिकॉर्ड बना रही है. लोकतंत्र के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में करोड़पति नेताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन जब बात अमीरी और अकूत धन-संपत्ति की आती है तो उच्च सदन यानी राज्यसभा के माननीय सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले लोकसभा सांसदों को काफी पीछे छोड़ देते हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो राज्यसभा सांसदों की औसतन संपत्ति लोकसभा सांसदों के मुकाबले करीब ढाई गुना ज्यादा है.

दोनों सदनों की अमीरी में कितना भारी अंतर? - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक, राज्यसभा के मौदूजा सांसदों की औसत घोषित संपत्ति 115.25 करोड़ रुपये है. इसकी तुलना में लोकसभा चुनाव में जीतकर आए सांसदों की औसत संपत्ति 46.34 करोड़ रुपये बैठती है. इस तरह से दोनों सदनों के सांसदों के बीच प्रति सांसद औसत करीब 69 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा फासला है. अगर कुल संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो राज्यसभा के 226 वर्तमान सदस्यों के पास कुल मिलाकर 26,047 करोड़ रुपये की अकूत धन-दौलत मौजूद है, जो कि देश की राजनीति में बड़े धनबल को दर्शाती है.

15 सालों में तेजी से बदले आंकड़े - भले ही औसत धन-दौलत के मामले में राज्यसभा आगे हो, लेकिन लोकसभा के अंदर भी करोड़पतियों की संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है. संसद के निचले सदन में कुल 543 में से 504 सदस्य करोड़पति हैं, यानी हर 100 में 93 सांसदों के पास एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. अगर पिछले 15 सालों का इतिहास टटोलें तो साल 2009 में केवल 58% लोकसभा सांसद करोड़पति थे. इसके बाद साल 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 82% हुआ, यह 2019 में 88% तक पहुंचा और अब यह सर्वकालिक उच्च स्तर 93% पर जाकर टिक गया है.

राज्यसभा में किस पार्टी के सांसद धन कुबेर? - उच्च सदन में क्षेत्रीय दलों के सांसदों की औसत संपत्ति राष्ट्रीय दलों के मुकाबले काफी हैरान करने वाली है. राज्यसभा में भारत राष्ट्र समिति BRS के महज 3 सांसदों की औसत संपत्ति 1841.39 करोड़ रुपये है. इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों की औसतन संपत्ति 399.71 करोड़, टीडीपी के सांसदों की 251.95 करोड़ और YSRCP के माननीय सदस्यों की औसत संपत्ति 170.88 करोड़ रुपये है. वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राज्यसभी सांसदों की औसत संपत्ति 76.46 करोड़ और कांग्रेस के सदस्यों की औसतन संपत्ति 130.37 करोड़ रुपये है.

किस पार्टी के लोकसभा सांसदों ने अमीरी में सबको पछाड़ा - लोकसभा के अंदर अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से औसत धन-दौलत का आकलन करें तो आंध्र प्रदेश ती तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सबसे अमीर पायदान पर खड़ी है. टीडीपी के 16 लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति 442.26 करोड़ रुपये है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की औसतन संपत्ति 50.04 करोड़, कांग्रेस के 99 सांसदों की 22.93 करोड़, डीएमके के 22 सांसदों की 31.22 करोड़ और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की औसत संपत्ति 15.24 करोड़ रुपये है. टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना जैसी कई पार्टियों के तो 100 फीसदी सांसद करोड़पति हैं.

दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही, 26 देशों के साथ 28 ऐतिहासिक समझौते ; विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या बताया

एजेंसी नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि भारत ने 26 देशों के साथ 28 प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौतों (एमएमपीए) या उनके समकक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों को लेकर बातचीत जारी है।

विदेश मंत्रालय द्वारा यहां आयोजित मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित करते हुए जयशंकर ने अवैध प्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि "विश्वसनीय और सुरक्षित आवागमन के मार्ग" मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। समुदायों के लिए मूल्य का सृजन उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गतिशीलता को एक "बहुत अहम स्तंभ" मानती है और ये साझेदारियां "आपसी फायदे, साझा जिम्मेदारी और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता" पर आधारित हैं। जब ऐसी साझेदारियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो इनसे स्रोत देशों, गंतव्य देशों, नियोक्ताओं, कामगारों और समुदायों के लिए मूल्य का सृजन होता है।

उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की जरूरत को भी समझते हैं। अब तक भारत ने 26 देशों के साथ 28 'प्रवास और गतिशीलता साझेदारी समझौते' (एमएमपीए) या उनके समान समझौते किए हैं और कई अन्य समझौतों पर अभी बातचीत चल रही है।

देशों की सामूहिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवास, शोषणकारी तौर-तरीकों, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये चुनौतियां कानूनी तौर पर आवाजाही के सिस्टम की विश्वसनीयता को कम करती हैं और कमजोर लोगों को जोखिम में डाल सकती हैं। इस मंच के लिए कई नीति-निर्माता, क्षेत्र के दिग्गज, नियोक्ता और पेशेवर इकट्ठा हुए हैं। इस मंच का मकसद विचारों का आदान-प्रदान करने, अनुभवों से सीखने और गतिशीलता के लिए नए तरीकों को खोजने के अवसर देना है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक "बड़े बदलाव" से गुजर रही है और इसी के तहत, अलग-अलग महाद्वीपों में आबादी के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवोन्मेष उद्योगों को अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमता, ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण और हरित बदलाव भी उन कौशलों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं जिनकी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन पुराने समय की चुनौतियां भी हमारे साथ बनी हुई हैं, चाहे वे स्वास्थ्य, उत्पादन, निर्माण या खेती से जुड़ी हों। साथ ही, समाज आपस में तेजी से जुड़ रहे हैं, और देशों की रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता भविष्य की समृद्धि की उनकी संभावनाओं पर काफी असर डालेगी। इसलिए, मानव संसाधन गतिशीलता का मतलब सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। यह "उम्मीदों को मौकों से जोड़ने" और "प्रतिभा को जरूरत से जोड़ने" के बारे में है।

पाकिस्तान बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे,एक्शन में भारत

एजेंसी नई दिल्ली

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला-चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। इस बार मुनीर के चेलों ने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ अपने आका मुनीर को खुश करने के लिए एक बयान देते हैं और अपने बयान में यह कहते हैं कि वह सिंधु जल का पानी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से जंग लड़ने को तैयार है। जनरल मुनीर के तमाम चेले चपाटे एक के बाद एक गीदड़ भभकी देने लगे। कोई यह कह रहा है अब कि हम पानी पर उठने वाले हर हाथ को काट देंगे। तो कोई यह कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है। दरअसल जुमले मुनीर के हैं जिससे उनके प्यादे दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी ने इनकी वो नस दबा कर रखी है जो कभी यह सपने में सोच भी नहीं सकते थे। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्यासी आवाम शहबाज और मुनीर से पानी मांग रही है और यह पूछ रही है कि जिस पानी को आप रेड लाइन कहते हो अब वो पानी क्यों नहीं ला रहे हो? दरअसल पाकिस्तान की जनता यह जान गई है कि पाकिस्तान में पानी संकट इनके हुक्मरानों की आतंकी गतिविधियों की वजह से खड़ा हुआ है। यह ना अपनी जमीन पर आतंकी पालते ना भारत पर पहलगाम जैसे हमले कराते और ना भारत सिंधु जल समझौता रद्द करता। लेकिन पाकिस्तान जो है यह अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाला है। शहबाज सरकार के एक मंत्री हैं मुसादिक मलिक। यह मुल्ले मौलानाओं की सभा में बैठकर एक ऐलान करते हैं, एक बयान देते हैं। गीदड़ भभकी देते हैं कि पाकिस्तान उन हाथों को काट देगा जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी रोकेगा। आपको बता दें कि मुसादिक मलिक जलवायु मंत्री है पाकिस्तान के अंदर। अब मुल्ले मलिक से कोई पूछे कि हिंदुस्तान ने तो सिंधु जल समझौता एक साल पहले ही रद्द कर दिया था। पाकिस्तान का पानी तो रुक चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पड़ी उसके जख्म तो भरे नहीं है। अब ये नई जंग का सोच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में यह जो पानी का मसला है यह एक बार फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक विवादित बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि पाकिस्तान पानी के लिए भारत से जंग लड़ने को तैयार है। तब से लेकर अब तक बिलावल भुट्टो सिंधु के पानी में खून बहाने की बात कर चुके हैं। अब मुसादिक मलिक हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। दरअसल बता दें कि भारत ने सिंधु संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। नदी के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। संदेश एक दूसरे को भेजे जाते थे। जल प्रवाह हो, बांध हो या फिर कोई परियोजना हो या जल प्रबंधन को लेकर लगातार संपर्क होता था दोनों देशों के बीच में। अब भारत ने इसी सपोर्ट पर रोक लगा दी है पिछले एक साल से। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। इसे वैश्विक बैंक ने करवाया था। कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा, कौनकितना इस्तेमाल करेगा, यह सब इसी समझौते से तय हुआ था। 1960 से लेकर अब तक यही समझौता दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी हरकतों ने इस बंटवारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए।

भारत ने की अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा, तालिबान खुश, बताया- सच्चा मित्र

एजेंसी काबुल

तालिबान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करने पर भारत को सच्चा मित्र करार दिया है। उसने कहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के हवाई हमलों पर खामोश रही, जबकि उसने एक देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया। वहीं, भारत ने एक सच्चे मित्र के जैसे खुलकर अफगानिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की निंदा की। भारत ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला करार दिया था और कहा था कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए सीधा खतरा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इन हमलों में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि तालिबान ने बताया कि इसमें 36 से अधिक आम अफगानी मारे गए हैं। तालिबान प्रशासित इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है और पाकिस्तान के हमलों की निंदा की है। इन हमलों में आम अफगान नागरिक हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। प्रवक्ता ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय सिद्धांतों और अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह अफगानी इलाके पर पाकिस्तान के हमलों की "कड़ी निंदा" करता है। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की जान गई है। मंत्रालय ने कहा, "पाकिस्तान की यह खुली आक्रामकता अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।" भारत ने पाकिस्तान पर "लापरवाही भरे व्यवहार का लगातार पैटर्न" अपनाने और सीमा-पार सैन्य कार्रवाई के ज़रिए अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामियों को बाहरी रूप देने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तानी हवाई हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और अफगानिस्तान की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। भारत का यह बयान तब आया जब अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने पुष्टि की कि रविवार रात पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 28 आम नागरिक मारे गए और 49 अन्य घायल हो गए। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये आंकड़े शुरुआती हैं और अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी रहने के कारण इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले की पुष्टि की है। उसने कहा कि तालिबान पाकिस्तान (TTP) और जमात-उल-अहरार के आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि, तालिबान ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया। तालिबान प्रशासित इस्लामिक अमीरात ने कहा कि पाकिस्तानी हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए।

ट्रंप को 'सुप्रीम' झटका, अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता; भारतीयों को बड़ी राहत

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता को बरकरार रखा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि अब जन्म के आधार पर विदेशी नागरिकों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गृह युद्ध के बाद अपनाए गए 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही समझ और हालिया संघीय कानूनों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति — बहुत कम अपवादों को छोड़कर — नागरिक है। तीन कंजर्वेटिव जजों ने इन प्रतिबंधों को लागू होने देने का समर्थन किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन प्रतिबंधों को कई निचली अदालतों ने रोक दिया था और ये अमेरिका में कहीं भी लागू नहीं हो पाए थे। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट की ओर से लिखते हुए कहा, "नागरिकता, तब और अब, अधिकारों को पाने का अधिकार थी — हमारे राजनीतिक समुदाय में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार। 14वें संशोधन को बनाने वालों ने यह वादा 'इस देश में स्वतंत्र रूप से जन्मे हर व्यक्ति' तक बढ़ाया था।" उन्होंने संशोधन पर कांग्रेस में हुई बहस का हवाला देते हुए कहा, "हम आज भी उस वादे को निभा रहे हैं।" अप्रैल में हुई बहस के दौरान, कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों तरह के जजों ने इस आदेश की वैधता पर सवाल उठाए थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था, और ट्रंप की कोर्टरूम में अभूतपूर्व मौजूदगी ने इसे और भी अहम बना दिया था। जन्म के आधार पर नागरिकता वाला यह आदेश, जिस पर ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए थे, उनके प्रशासन की आव्रजन (इमिग्रेशन) के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। जन्म के आधार पर नागरिकता का मुद्दा ट्रंप की आव्रजन-संबंधी पहली ऐसी नीति थी जो अंतिम फैसले के लिए कोर्ट तक पहुंची। इससे पहले जजों ने उन वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को रद्द कर दिया था जिन्हें ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत लागू किया था — जबकि उस कानून का इस्तेमाल पहले कभी इस तरह नहीं किया गया था। जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों को नागरिकता नहीं देने की बात कही गई थी, जिनके माता-पिता गैरकानूनी तरीके से या अस्थायी वीजा पर देश में रह रहे हों। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाला हर भारतीय बच्चा वहां का नागरिक होगा। इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी, जो ट्रंप के फैसले से तनाव में थे।

भारत आने के लिए बेताब बांग्लादेशी! वीजा सेंटर खुलते ही उमड़ा हुजूम, लोगों की लंबी लाइन

एजेंसी ढाका

बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र दो साल बाद फिर खुल गए हैं। राजधानी ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के बाहर लंबी लाइन देखी गई है। लोग भारत का पर्यटक वीजा पाने के लिए बेचैन दिखे। कई लोग मेडिकल वीजा के लिए भी लाइन में खड़े थे, जिन्हें अपने सगे संबंधियों को इलाज के लिए भारत ले जाना था। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तल्खी आ गई थी। इसके बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा को बंद कर दिया था, लेकिन मेडिकल वीजा तब भी जारी रहा। 25 जून को, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने घोषणा की थी कि 28 जून, 2026 से पांच वीजा केंद्रों से टूरिस्ट वीजा सर्विस फिर से शुरू होंगी, जिनमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका का भारतीय वीजा आवेदन केंद्र भी शामिल है। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र सौंपने के बाद यह घोषणा की थी। उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पिछले गुरुवार को राष्ट्रपति भवन, बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा था। अपना परिचय पत्र सौंपने के बाद, उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने वीजा से जुड़े कामकाज का जायजा लेने के लिए जमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) का दौरा किया और टूरिस्ट वीज़ा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय स्टाफ और बांग्लादेशी नागरिकों से मुलाकात भी की थी। कई बांग्लादेशी नागरिकों ने उनसे ज्यादा ज्यादा संख्या में वीजा जारी करने का अनुरोध भी किया था। कुछ ने मेडिकल वीजा में बढ़ोत्तरी की मांग की थी। 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद धनमंडी स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में बुरी तरह तोड़-फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के अलग-अलग शहरों में पांच इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटरों (IVACs) पर हमले हुए और विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को धमकियां दी गईं। सुरक्षा खतरों और हाई कमीशन परिसर पर हमलों के कारण, भारत ने बांग्लादेश में वीजा सेवाओं को सीमित कर दिया था।

सीजफायर के बाद पहली बार पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

एजेंसी नई दिल्ली

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। यह दोनों नेताओं के बीच संघर्षविराम के बाद पहली बातचीत थी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति और आगे की रणनीति से अवगत कराया।

पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में पश्चिम एशिया में हुए इस संघर्षविराम का स्वागत किया। उन्होंने कहा, सभी मुद्दों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।

पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान विशेष रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता के लिए समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुआ शांति समझौता ज्ञापन (एमओयू) ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के साथ पूरी तरह तालमेल और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) के समर्थन से तैयार किया गया है।

मध्य ईरान के कोम प्रांत के दौरे के दौरान पेजेश्कियन ने कहा, 'अमेरिका के साथ बातचीत के सभी चरण ईरानी सरकार की बड़ी नीतियों के दायरे में, सर्वोच्च नेता के साथ लगातार और पूरी तरह तालमेल बनाकर और देश के कानूनी नियमों के अनुसार आगे बढ़ाए गए।'

पेजेश्कियन ने कहा कि यह एमओयू ईरानी लोगों के लिए एक कूटनीतिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अंतिम समझौते तक पहुंचने की बातचीत में ईरान अपने लोगों के अधिकारों, अपने मूल सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा।

18 जून को ईरान और अमेरिका ने क्षेत्र में चल रहे युद्ध को सभी मोर्चों पर खत्म करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। दोनों देश अब एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत को लेकर।

एमसीसी का मिला आजीवन सम्मान, चेतेश्वर पुजारा बोले- इंग्लैंडलगता है दूसरा घर

नई दिल्ली, एजेंसी | चेतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर के दौरान आस्ट्रेलिया में कुछ बेहतरीन पारियां खेली लेकिन हाल ही में एमसीसी की आजीवन सदस्यता पाने वाले इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि इंग्लैंड उन्हें दूसरे घर जैसा लगता है। भारतीय टीम के साथ तीन बार इंग्लैंड का दौरा करने वाले पुजारा काउंटी क्रिकेट में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने राजकोट के बाद अपना सबसे अधिक समय इंग्लैंड में बिताया है।

प्रसिद्ध लॉर्ड्स स्टेडियम में स्थित मैरीलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित पुजारा ने कहा, ''मैं काउंटी क्रिकेट में काफी खेला हूं। इसलिए जब आप वहां बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो आपको घर जैसा महसूस होने लगता है। मेरे लिए एमसीसी का हिस्सा बनना बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है।'' इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने पीटीआई को दिए गए साक्षात्कार में कहा, ''एमसीसी की मानद सदस्यता मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

एक क्रिकेटर के तौर पर जब आपने अपने पूरे करियर में कड़ी मेहनत की हो और जब उसे पहचान मिले तो फिर आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है।'' पुजारा ने लॉर्ड्स में जो तीन टेस्ट मैच खेले हैं, उनमें से भारत ने दो मैच जीते। भारत की तरफ से वह इस ऐतिहासिक मैदान पर शतक नहीं लगा पाए लेकिन उन्होंने ससेक्स की तरफ से खेलते हुए यहां दोहरा शतक लगाया है। भारत की तरफ से 103 टेस्ट मैच खेलने वाले पुजारा दुनिया के सभी प्रसिद्ध मैदानों पर खेले हैं लेकिन लॉर्ड्स में खेलने का अनुभव कुछ अलग ही होता है। उन्होंने कहा, ''लॉर्ड्स में क्रिकेट खेलने और वहां क्रिकेट देखने की मेरी कुछ अच्छी यादें हैं।

2011 में मेरे घुटने की सर्जरी लंदन में हुई थी और इसके लिए जब मैं वहां डॉक्टर से सलाह ले रहा था, तो मैंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का का दौरा किया। क्योंकि उससे पहले मैं कभी लॉर्ड्स में नहीं खेला था।'' पुजारा ने कहा, ''जब आप उस मैदान में कदम रखते हैं, तो उसका एक अलग ही माहौल और अलग ही ऊर्जा होती है। जब आप एमसीसी के आजीवन सदस्य बन जाते हैं, तो आपको वहां जाकर क्रिकेट देखने का विशेषाधिकार मिल जाता है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं वहां क्रिकेट खेलूं।'' लॉर्ड्स में खेलना चुनौतीपूर्ण है और पुजारा ने भी यह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ''वहां की पिच पर जमने में समय लगता है। एक बल्लेबाज के रूप में आपको क्रीज पर पर्याप्त समय बिताना होता है और फिर अपने शॉट खेलने शुरू करने होते हैं।

इसलिए यह किसी भी बल्लेबाज के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण पिच है। यदि आप वहां की ढलान से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है।'' पुजारा ने कहा, ''इसके लिए आपको अपने बल्लेबाजी के तरीके में कुछ बदलाव करने होते हैं। लेकिन एक बार जब आप उससे सामंजस्य से बिठा लेते हैं तो यह बल्लेबाजी के लिए एक शानदार पिच है। उसकी आउटफील्ड भी काफी शानदार है। अगर मैं अपने क्रिकेट करियर में कुछ बदलना चाहूं, तो मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में शतक बनाना एक बड़ी उपलब्धि होती।''

पुजारा का ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रिकॉर्ड रहा है लेकिन भारत के बाद इंग्लैंड वह जगह है जहां उन्होंने अपने खेल का भरपूर का आनंद लिया। उन्होंने कहा, ''जहां तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा रिकॉर्ड शानदार रहा है। मुझे वहां बल्लेबाजी करना पसंद था। ऑस्ट्रेलिया में एक बार निगाह जम जाने के बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होता है।'' पुजारा ने कहा, ''इंग्लैंड में खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अब चीजें कुछ बदल गई हैं और आज की पिचें पहले की पिचों से थोड़ा अलग हैं।

एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंटः सेंथिलकुमार की जीत के साथ शुरुआत, सेमवाल और शमीना बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी | एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट में बुधवार को टॉप सीड वेलवन सेंथिलकुमार ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि ओम सेमवाल को हार का सामना करना पड़ा।

मुंबई स्थित जुहू विले पार्ले जिमखाना क्लब में जारी 15,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में सेंथिलकुमार ने बिना किसी खास परेशानी के अयान वजीरल्ली को 11-4, 11-9, 11-6 से शिकस्त दी। चौथी सीड हाफेज और 7वीं सीड एंडो भी सीधे गेम में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

मंगलवार को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में तीसरी सीड को हराने वाले सेमवाल, मिस्र के 8वीं सीड जियाद इब्राहिम के खिलाफ भी एक और उलटफेर भरी जीत की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि, 22 वर्षीय खिलाड़ी अंतिम चरणों में थोड़े लड़खड़ा गए और एक कड़े फैसले वाले गेम में हार गए।

जर्मनी के गोल पर मचे बवाल के बीच फीफा का बड़ा बयान, बताया वीएआर का फैसला क्यों सही था

नई दिल्ली, एजेंसी | विश्व फुटबॉल की एक सर्वोच्च संस्था फीफा ने जर्मनी के संभावित निर्णायक गोल को अमान्य ठहराए जाने पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा नियमों के तहत किया गया। परागवे के खिलाफ सोमवार को खेले गए मैच में अतिरिक्त समय में जर्मनी के डिफेंडर जोनाथन ताह ने हेडर से गोल कर दिया था लेकिन वीडियो समीक्षा (वीएआर) के बाद इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि परागवे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल पर फाउल किया गया था।

रीप्ले में जर्मनी के वाल्डेमार एंटोन को गिल को हल्का धक्का देकर जमीन पर गिराते हुए दिखाया गया।

यह मामूली संपर्क था जिसके कारण इस फैसले की आलोचना हो रही है। जर्मनी पेनल्टी शूटआउट में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फीफा के रेफरी विभाग के प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी खिलाड़ी जब गेंद लेने के बजाय विरोधी टीम के खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करता है तो ऐसी घटनाओं पर दंडित किया जाए, खासकर तब जबकि इसमें गोलकीपर शामिल हों।

उन्होंने कहा, ''अपनी जगह पर खड़े रहना अपने आप में कोई फाउल नहीं है, लेकिन जब आक्रमण करने वाली टीम का कोई खिलाड़ी गेंद लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाता और जानबूझकर थोड़ा सा ही सही, विपक्षी खिलाड़ी की गतिविधि में बाधा डालने और उसेबचाव करने से रोकने के स्पष्ट इरादे से हिलता है, तो रेफरी को वीएआर के जरिये विश्लेषण करना चाहिए और उचित हस्तक्षेप करना चाहिए।''

कोलिना ने कहा, ''यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब इस रणनीति का उद्देश्य विपक्षी गोलकीपर को गोल का बचाव करने से रोकना हो। कोच और खिलाड़ियों को पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था।

विंबलडन 2026 : ब्रिटेन को घर में डबल झटका, एमा राडुकानू के बाद पहले ही दिन सभी 10 खिलाड़ी बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी | विंबलडन 2026 की शुरुआत मेजबान ब्रिटेन के लिए उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही देश के दो सबसे बड़े टेनिस सितारे एमा राडुकानू और जैक ड्रेपर चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके बाद पहले दिन कोर्ट पर उतरे घरेलू खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा। मौजूद जानकारी के अनुसार, अपने पहले दौर के मुकाबले पूरे करने वाले सभी 10 ब्रिटिश खिलाड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए, जबकि एक अन्य खिलाड़ी का मुकाबला खराब रोशनी के कारण बीच में रोकना पड़ा।

बता दें कि वर्ष 2021 में अमेरिका ओपन जीतकर दुनिया को चौंकाने वाली एमा राडुकानू ने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पैर में तनावजनित फ्रैक्चर के कारण अपना नाम वापस ले लिया। हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा था। इसी महीने उन्होंने क्वींस क्लब घास के कोर्ट प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचकर शानदार लय दिखाई थी। ऐसे में घरेलू दर्शकों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उधर ब्रिटेन के शीर्ष पुरुष खिलाड़ी जैक ड्रेपर ने भी लंबे समय से चली आ रही हाथ की चोट के कारण विंबलडन से हटने का फैसला किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष वह प्रतियोगिता में चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे और वर्ष 2024 के अमेरिका ओपन के सेमीफाइनल तक भी पहुंचे थे।

मैक्सिको का 40 साल का इंतजार खत्म, क्विनोन्स और जिमेनेज के गोल से इक्वाडोर को 2-0 से रौंदा

नई दिल्ली, एजेंसी | जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज ने पहले हाफ में नौ मिनट के अंतराल में गोल किए जिससे मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और नॉकआउट चरण में जीत हासिल करने के 40 साल के सूखे को खत्म किया। क्विनोनेस ने 22वें मिनट में मैक्सिको के लिए पहला गोल किया जबकि जिमेनेज ने 31वें मिनट में उसकी बढ़त दोगुनी कर दी। मैक्सिको की टीम ने 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए राउंड ऑफ 16 में बुल्गारिया को हराने के बाद से नॉकआउट चरण का कोई मैच नहीं जीता था।

इसके बाद मैक्सिको को 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 के विश्व कप में अंतिम 16 में लगातार सात बार हार का सामना करना पड़ा। वह कतर में 2022 में खेले गए विश्व कप में ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया था। मैक्सिको रविवार को अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड और कांगो के बीच बुधवार को होने वाले मैच के विजेता का सामना करेगा। यह टूर्नामेंट में क्विनोनेस का तीसरा गोल था और अब वह विश्व कप इतिहास में एल ट्राइ (मैक्सिको की टीम का उपनाम) की तरफ से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

उनसे आगे लुई हर्नांडेज़ और जेवियर हर्नांडेज़ हैं, जिन्होंने चार-चार गोल किए थे। जिमेनेज़ ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल किया और उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 47 गोल करके जेरेड बोर्गेटी को पीछे छोड़ दिया। वह अब मैक्सिको की तरफ से सर्वाधिक गोल करने के मामले में जेवियर हर्नांडेज़ की बराबरी करने से सिर्फ पांच गोल दूर हैं। प्रतिष्ठित एज़्टेका स्टेडियम में मैक्सिको की टीम ने 10 विश्व कप मैचों में अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाया है।

इस मैदान पर मैक्सिको को केवल दो हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से आखिरी हार उसे छह सितंबर, 2013 को होंडुरास के खिलाफ विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में मिली थी। इक्वाडोर अपने इतिहास में दूसरी बार और जर्मनी में 2006 में खेले गए विश्व कप के बाद पहली बार राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की कोशिश कर रहा था।

आंधी-तूफान के कारण मैच निर्धारित समय से एक घंटे देरी से शुरू हुआ। मौसम से प्रभावित होने वाला यह टूर्नामेंट का दूसरा मैच था। फ्रांस और इराक के बीच 22 जून को फिलाडेल्फिया में खेले गए मैच के दौरान तूफान के कारण पहले हाफ के आखिर में दो घंटे 11 मिनट तक खेल नहीं हो पाया था।

व्यापार

जीएसटी कलेक्शन में उ.प्र. ने मारी बाजी, 19% की बढ़ोत्तरी के साथ बना देश का सिरमौर

जून 2026 में जीएसटी संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश 19% की बढ़ोतरी के साथ राज्यों में सबसे आगे रहा, जबकि झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के राजस्व में गिरावट देखी गई।

नई दिल्ली, एजेंसी | देश की कर व्यवस्था से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। जून 2026 में जीएसटी संग्रह में पिछले 13 महीनों की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई है। मौजूद जानकारी के अनुसार, जून महीने में सकल जीएसटी संग्रह 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। एक वर्ष पहले जून 2025 में यह आंकड़ा 1.71 लाख करोड़ रुपये था। इससे पहले मई 2026 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर केवल 3.2 प्रतिशत रही थी, जबकि जून में इसमें तेज सुधार देखने को मिला हैं।

बता दें कि जून 2026 की यह वृद्धि मई 2025 के बाद सबसे अधिक मानी जा रही है। मई 2025 में जीएसटी संग्रह में 16.4 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत कर संग्रह सरकार के राजस्व के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे आर्थिक गतिविधियों की स्थिति का भी अंदाजा लगाया जाता है।

इस बार जीएसटी संग्रह में सबसे बड़ा योगदान आयात से मिलने वाले टैक्स का रहा। आयात पर मिलने वाला जीएसटी 34.6 प्रतिशत बढ़कर 60,038 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 44,600 करोड़ रुपये था। इससे साफ है कि विदेशों से होने वाले आयात पर कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

दूसरी ओर, घरेलू कारोबार से मिलने वाले सकल जीएसटी संग्रह में अपेक्षाकृत धीमी बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू कर संग्रह 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे संकेत मिलता है कि जून महीने में कुल कर संग्रह बढ़ाने में आयात का योगदान घरेलू व्यापार की तुलना में अधिक रहा है।

गौरतलब है कि कर वापसी की राशि भी इस दौरान काफी अधिक रही। जून में कुल 32,436 करोड़ रुपये की कर वापसी की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। कर वापसी के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 11.2 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा।

यदि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 की बात करें तो इस दौरान सकल जीएसटी संग्रह 8.4 प्रतिशत बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं शुद्ध संग्रह 7.1 प्रतिशत बढ़कर 5.40 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष की शुरुआत सकारात्मक रही है, हालांकि सभी क्षेत्रों में समान गति से बढ़ोतरी नहीं हुई है।

राज्यों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राज्य में जून के दौरान जीएसटी संग्रह 19 प्रतिशत बढ़कर 9,165 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 7,675 करोड़ रुपये था। असम में 17 प्रतिशत, पंजाब में 14 प्रतिशत और गुजरात में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

देश में सबसे अधिक जीएसटी योगदान देने वाले महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वहां संग्रह 9 प्रतिशत बढ़कर 30,714 करोड़ रुपये पहुंच गया। कर्नाटक में 10 प्रतिशत और दिल्ली में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

हालांकि सभी राज्यों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीएसटी संग्रह 5-5 प्रतिशत घट गया। तमिलनाडु में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि झारखंड में सबसे अधिक 16 प्रतिशत की कमी देखने को मिली हैं।

गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यापारिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। मजबूत कर संग्रह से सरकार की आय बढ़ती है, जिससे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता भी मजबूत होती है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि जीएसटी संग्रह की यह रफ्तार लगातार बनी रहती है या नहीं।

मोदी कैबिनेट का दिल्ली को तोहफा, द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6-लेन टनल

प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच तेज़ी से कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि यह UER 2/द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज से जोड़ेगा।

नई दिल्ली, एजेंसी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 14,115 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट में NH-148AE के लिए 6-लेन वाली सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच तेज़ी से कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि यह UER 2/द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज से जोड़ेगा।

प्रोजेक्ट की लागत - 8.1 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट NH (O) स्कीम के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) में कुल 6,969.67 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा, 'अंडरग्राउंड ट्विन-ट्यूब टनल से ज़मीन पर होने वाली रुकावट कम से कम होगी और सदर्न रिज फ़ॉरेस्ट सुरक्षित रहेगा (टनल का 1.98 किलोमीटर हिस्सा रिज के नीचे से गुज़रेगा)। NHAI, AIIMS और महिपालपुर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव दे रहा है। यह लिंक टनल को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, जिससे वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा से जुड़ जाएंगे।

रोज़गार के अवसर - अनुमान है कि नेशनल हाईवे के हर लेन-किलोमीटर के विकास से औसतन 264 पर्सन-डेज़/दिन का डायरेक्ट रोज़गार और औसतन 55 पर्सन-डेज़/दिन का इनडायरेक्ट रोज़गार पैदा होता है। इसलिए, इस प्रोजेक्ट से लगभग 7.54 लाख पर्सन-डेज़ का डायरेक्ट रोज़गार और 9.80 लाख पर्सन-डेज़ का इनडायरेक्ट रोज़गार पैदा होगा।

उत्तर प्रदेश में सड़क प्रोजेक्ट - कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में NH-34 के 117.7 किलोमीटर लंबे, 4/6-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड कानपुर-कन्नई सेक्शन के निर्माण को भी मंज़ूरी दे दी है। प्रस्तावित हाई-स्पीड कॉरिडोर के आस-पास आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से इस प्रोजेक्ट से रोज़गार के और भी अवसर पैदा होंगे।

जून में बिजली की रिकार्ड उंची मांग, खपत 11.62% बढ़ी, जानें क्या है पावर ग्रिड पर इसका असर

भीषण गर्मी और मानसून में देरी के कारण जून में देश की बिजली की खपत 11.62% बढ़कर 166.46 अरब यूनिट हो गई। एयर कंडीशनर जैसे कूलिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने बिजली की अधिकतम मांग को भी 264.76 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया, जो ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

नई दिल्ली, एजेंसी | देश में भीषण गर्मी पड़ने और मानसून में देरी के कारण जून में बिजली की खपत 11.62 प्रतिशत बढ़कर 166.46 अरब यूनिट रही। मानसून में देरी और गर्मी के कारण एयर कंडीशनर जैसे ठंडक देने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। देश में कुल बिजली खपत बीते वर्ष जून में 149.13 अरब यूनिट थी। पिछले महीने बिजली की अधिकतम मांग भी बढ़कर 264.76 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर 1,000 मेगावाट) हो गई, जो जून, 2025 में 242.77 गीगावाट थी।

दक्षिण-पश्चिम मानसून चार जून, 2026 को केरल पहुंचा था। आम तौर पर, मानसून एक जून के आसपास केरल पहुंचता है। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून आने (जून-सितंबर) का शुरुआत का संकेत होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून में मानसून की धीमी गति के कारण लू की स्थिति बनी। इससे एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर जैसे 'कूलिंग' उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा। इससे बिजली की मांग और खपत बढ़ी है। उनका मानना है कि जुलाई में बिजली की मांग स्थिर रहेगी, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बारिश में थोड़ी कमी का अनुमान लगाया है।

बिजली की अधिकतम मांग मई, 2026 में बढ़कर 270.82 गीगावट के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि 2025 में इसी महीने में यह 230.99 गीगावाट रही थी। इस साल मई में लगातार चार दिन तक बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड स्तर पर रही।

18 मई को यह 257.37 गीगावाट, 19 मई को 260.45 गीगावाट, 20 मई को 265.44 गीगावाट और 21 मई को 270.82 गीगावाट रही थी। बिजली मंत्रालय के अनुसार, इस साल गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। बिजली की अधिकतम मांग पिछली गर्मियों में, जून में 242.77 गीगावाट रही थी। हालांकि, यह सरकार के 277 गीगावाट के अनुमान से कम रही।

ऑटिज्म बीमारी नहीं, समझ और अपनापन चाहिए'

ईशा सिंह ने समाज की सोच पर उठाए सवाल

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह इन दिनों अपने आने वाले शो 'जूही मुई' को लेकर चर्चा में हैं। इस शो में वह अपने करियर का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने जा रही हैं। ईशा इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाली लड़की 'जूही' की भूमिका में नजर आएंगी।

अपने इस किरदार की तैयारी और ऑटिज्म को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों पर अभिनेत्री ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में लोग ऑटिज्म को बीमारी समझते हैं, जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में ईशा सिंह ने कहा, ''आज भी बहुत से लोग ऑटिज्म को सही तरीके से नहीं समझते। जागरूकता की कमी पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी देखने को मिलती है। मेरे अपने दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी नहीं है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग इस विषय को समझें और इसके बारे में सही जानकारी हासिल करें।'' ईशा सिंह ने कहा, ''ऑटिज्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे बीमारी मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। कुछ माता-पिता यह सोचते हैं कि ऑटिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जबकि यह पूरी तरह गलत धारणा है। ऑटिज्म न तो संक्रामक है और न ही यह किसी तरह की बीमारी है।''

अभिनेत्री का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले बच्चे अक्सर बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और प्यार करने वाले होते हैं। उन्हें समाज से सहानुभूति नहीं बल्कि समझ और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के साथ दुनिया में आता है।

अपने नए शो में निभाए जा रहे किरदार को लेकर ईशा सिंह ने कहा, ''यह मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रोल है। चूंकि यह एक बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए मैंने इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा उद्देश्य ऑटिज्म से जुड़े लोगों की भावनाओं और व्यवहार को पूरी ईमानदारी के साथ दर्शकों तक पहुंचाना था।''

ईशा ने कहा, ''इस किरदार की तैयारी के दौरान मैंने ऑटिज्म पर आधारित कई इंटरव्यू देखे, विशेषज्ञों और लोगों से बातचीत की, इस विषय पर काफी रिसर्च की और कई किताबें भी पढ़ीं। यह सीखने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जूही का किरदार निभाते हुए मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैंने अपने स्टडी, लोगों के अनुभव और अपनी व्यक्तिगत समझ को मिलाकर इस किरदार को तैयार किया है।''

अभिनेत्री ने बताया, ''जूही के किरदार के लिए मुझे अपने चलने, बोलने, बैठने, प्रतिक्रिया देने और भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर भी बारीकी से काम करना पड़ा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले लोग हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसे सामान्य तरीके से व्यक्त कर पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अभिनय में किसी तरह का दिखावा नहीं रखा, बल्कि छोटे-छोटे हाव-भाव और स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया।'' ईशा सिंह ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि जब दर्शक 'जूही मुई' देखेंगे तो उन्हें मेरे किरदार की कई ऐसी बारीकियां नजर आएंगी, जिन पर पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। अगर इस शो के जरिए कुछ लोग भी ऑटिज्म को लेकर अपनी सोच बदलते हैं और इसे सही तरीके से समझ पाते हैं, तो मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी।''

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर अपने आध्यात्मिक और निजी पलों को लेकर सुर्खियों में हैं। मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीजियो पोस्ट की, जिसमें वह अपने पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चडा के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करती दिख रही हैं।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में राघव चड्ढा संग पहुंचीं परिणीति चोपड़ा

वीडियो में परिणीति पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। पूजा के दौरान उन्होंने अपने सिर को पल्लू रखा हुआ है। वहीं राघव चड्ढा भी ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखाई दिए। दोनों मंदिर में भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखे। उन्होंने विधि-विधान के साथ आरती भी की। इस वीडियो के साथ परिणीति ने कैप्शन लिखा, ''मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान एक शांत सुबह में शिव स्तुति 'नमामि शमिशम' को रिकॉर्ड करने का फैसला किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे इतना प्यार मिलेगा। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि यह आपकी सुबह की प्लेलिस्ट में शामिल हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे यह सालों से हमारे परिवार की आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा रही है।'' उनके इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि अपने पोस्ट में उन्होंने जिस शिव स्तुति 'नमामि शमिशम' का जिक्र किया है, उसे हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था। इसको गीत को लेकर परिणीति ने बताया था कि यह गीत उनकी जिंदगी का एक भावुक अध्याय की याद बन गया है। जब भी वह इस गीत को सुनती हैं, तो उन्हें अपनी गर्भावस्था का सुंदर समय याद आता है। अब अगर इस कपल की लव स्टोरी की बात करें, तो परिणीति और राघव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। दोनों की पहली मुलाकात लंदन में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान हुई थी, जहां दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में सम्मान मिला था।

शुरुआत में यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें राघव ने उन्हें ब्रेकफास्ट मीटिंग पर आने के लिए कहा। यहीं से दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री बनने लगी। दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलने लगे। फिल्म 'चमकीला' की शूटिंग के लिए जब परिणीति पंजाब में थीं, तो राघव उनसे मिलने वहां पहुंचे थे। दोनों ने जल्द ही अपना रिश्ता सार्वजनिक किया और मई 2023 में सगाई कर ली। इसके बाद 24 सितंबर 2023 को दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की

आईने के सामने खुद को देख रो पड़ती थीं अविका गौर

13 किलो वजन घटाकर किया असली ट्रांसफॉर्मेशन

30 जून 1997 को मुंबई में जन्मीं अविका गौर ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2007 में उन्होंने 'शश्श...कोई है' से छोटे रोल के जरिए टीवी डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में आए शो 'बालिका वधू' से मिली। इस शो में उन्होंने छोटी आनंदी का किरदार निभाया, जो एक बाल विवाह की कहानी पर आधारित था। उनके मासूम अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और वह बहुत जल्दी घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद अविका ने 'ससुराल सिमर का' में रोली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा लड़की की भूमिका निभाई। यह रोल उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था। इस शो ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। इसमें उनकी और अभिनेता मनीष रायसिंघन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने 2009 में 'मॉर्निंग वॉक' और 'पाठशाला' जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'उय्याला जम्पला' से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी आया जब अविका अपने शरीर और आत्मविश्वास को लेकर संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने खुद बताया था कि एक समय वह आईने में खुद को देखकर टूट गई थीं और रो पड़ी थीं। उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, नियमित वर्कआउट शुरू किया और अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव के जरिए उन्होंने करीब 13 किलो वजन कम किया और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने खुद को वैसे स्वीकार करना सीखा जैसा वह हैं। इसी बीच अविका ने रियलिटी शोज जैसे 'खतरों के खिलाड़ी 9' और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें वह लीड रोल में नजर आईं। अपने करियर में अविका गौर ने कई अवॉर्ड्स हासिल किए, जिनमें आईटीए सर्टिफिकेट और एसआईआईएमए अवॉर्ड शामिल हैं।

अभिनेत्री अविका गौर ने टीवी स्क्रीन पर मासूम 'आनंदी' बनकर घर-घर में पहचान बनाई, लेकिन एक समय उन्हें अपनी जिंदगी में खुद से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की प्राची सिंह बोली

इस इंडस्ट्री में टिकना है तो मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी

टीवी इंडस्ट्री में कलाकारों को रोज नए किरदार निभाने पड़ते हैं, लंबे समय तक शूटिंग करनी होती है और हर दिन बेहतर परफॉर्म करने का दबाव भी रहता है। ऐसे माहौल में खुद को एक्टिव रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसी मुद्दे पर अब टीवी अभिनेत्री प्राची सिंह ने विचार साझा किए हैं। इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में मंजरी उर्फ मुन्नी का किरदार निभा रहीं प्राची का कहना है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सिर्फ अच्छा अभिनेता होना काफी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत और जमीन से जुड़ा रहना भी बेहद जरूरी है। प्राची सिंह ने से बात करते हुए कहा, ''यह काम बहुत चुनौती भरा है। ऐसे में मानसिक सेहत का ध्यान रखना और सही सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में बहुत धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप छोटी-छोटी बातों से परेशान होने लगेंगे, तो लंबे समय तक यहां टिक पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है।'' उन्होंने कहा, 'परिवार और अपनी जड़ों से जुड़े रहना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है, तो एक अलग सुकुन मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान हमेशा खुद जैसा है, वैसा ही रहे। दिखावे में जीने से मन कभी शांत नहीं रहता। ' प्राची ने कहा, 'सफलता मिलने के बाद भी इंसान को विनम्र बने रहना चाहिए। मनोरंजन की दुनिया में जमीन से जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल जरूर होता, लेकिन अगर इंसान व्यवहार और सोच को नहीं बदलता, तो वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। मैं चाहूंगी कि हर कलाकार सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बना रहे।'' बातचीत के दौरान प्राची सिंह ने अभिनय के तरीके के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए इमोशनल सीन्स सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। ऐसे सीन्स में मैं सोचती हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसा महसूस करती और कैसी प्रतिक्रिया देती।

रोटरी क्लब गाडरवारा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) गत दिवस स्थानीय सुरभि पैलेस होटल में इस वर्ष के नवीन सत्र 2026-2027 के लिए रोटरी क्लब गाडरवारा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में क्लब के नये पदाधिकारियों अध्यक्ष शरद मौलासरिया, सचिव संजय गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष शुभम राजपूत क़ो शपथ अधिकारी रोटेरियन एस आर मिश्रा द्वारा शपथ दिलाई गई एवं उनका बैच लगाकर सम्मान किया गया।

अतिथियों द्वारा भगवान श्री गणेश पूजन से शुरू हुए इस आयोजन में रोटरी क्लब की गतिविधियो में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले सहयोगियो का सम्मान क्लब के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में डाक्टर्स डे एवं सीए डे के अवसर पर क्लब में शामिल डाक्टर्स एवं सीए सदस्यों क़ो भी सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षक मधुसूदन पटैल एवं कंछेदी धानक क़ो क्लब में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उदबोधन के क्रम में सर्वप्रथम निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र साहू ने स्वागत भाषण देते हुए उनके कार्यकाल में आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियो का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्हें सभी का भरपूर सहयोग मिला। क्लब के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर मिनेन्द्र डागा ने अपने उदबोधन में रोटरी क्लब के इतिहास एवं अवधारणा से जुडी जानकारी देते हुए क्लब के सहयोगी सदस्यों की प्रशंसा की एवं कहा कि प्रत्येक सदस्य के सहयोग से ही क्लब की गतिविधियो का बेहतर ढंग से संचालन हो पाता है। क्लब के नवागत अध्यक्ष शरद मौलासरिया ने अपने उदबोधन में अपनी आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया एवं कहा कि क्लब के हर सदस्य का सहयोग मुझे मिलेगा। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संदीप भूरिया एडिशनल एस.पी. नरसिंहपुर ने उपस्थित न होने के बावजूद मोबाइल से उदबोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन सचिव मनोज वशा ने किया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी आश्रम से प्रीति दीदी,असिस्टेंट गवर्नर अशोक राजपूत सहित रोटरी क्लब के सदस्यों एवं समाजसेवी संगठनों की उपस्थिति रहीं

अटल बिहारी मंदिर में नौका विहार उत्सव आयोजित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) विगत दिवस मंगलवार क़ो स्थानीय श्रीदेव अटल बिहारी मंदिर में भव्य नौका विहार उत्सव का आयोजन शाम 6 बजे से किया गया । मंदिर के पुजारी कमलेश भार्गव के मार्गदर्शन में आयोजित नौका विहार उत्सव में भगवान श्री कृष्ण का नौका में अलौकिक श्रृंगार एवं विहार आकर्षण का केंद्र रहा। उत्सव के आयोजन हेतु मंदिर में एक बड़े, चोड़े एवं गहरे पात्र मे पानी एकत्रित कर उसमे भगवान श्री कृष्ण क़ो नौका बिहार कराया गया। इस दौरान मंदिर में भव्य आरती एवं भजनों का आयोजन भी हुआ। अंत में प्रसाद वितरण उपरांत कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम में श्रीदेव अटल बिहारी भक्त मंडल के आह्वान पर अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे

झमाझम बारिश से नगर हुआ तरबूतर लोगों को गर्मी से मिली राहत

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) मानसून की दस्तक और लंबे समय से हो रहा झमाझम बारिश का इंतजार जुलाई की पहली दस्तक आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की दूज बुधवार को दोपहर उपरांत पहले तो आकाश में छाए सघन काले बादल इसके बाद गर्जन के साथ करीब एक-डेढ घंटे नगर में हुई झमाझम बारिश जिससे नगर तरबतर हो उठा। बारिश के दौरान नगर के नाला नाली दिखे उफान पर इसके साथ ही कॉलोनियों में भी झमाझम बारिश के चलते जल भराव देखा गया पर्याप्त पानी की निकासी न होने से कॉलोनी एवं खाली प्लॉट मैदान आदि स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई जबकि अभी तो थोड़ी सी बारिश में यह हालत हैं ता आगे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी वर्षा काल में क्या हालत हो सकते हैं समय रहते नपा को इस और ध्यान देने की महती आवश्यकता है। झमाझम बारिश के दौरान बच्चों ने जमकर झमाझम बारिश का भीगते हुए लुफ्त उठाया। झमाझम बारिश हो जाने के बावजूद आकाश में सघन बादल छाए रहे बहरहाल झमाझम बारिश हो जाने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की आगे मौसम किस ओर करवट बदलेगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। किसानों का मानना है कि इस तरह की बारिश से खेती जमीन में नमी होगी साथ ही धान की खेती के लिए बरसात वरदान साबित हो सकेगी

सालीचौका में 4 जुलाई को 'एक शाम शहीदाने कर्बला के नाम

मशहूर सूफी कलाकार शवेज शरफत वारसी पेश करेंगे शहीदी कव्वाली

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा । (राजेश नीरस) यौम-ए-आशूरा के बाद अब शहीदाने कर्बला की याद में सालीचौका मोहर्रम कमेटी व कौमी एकता कमेटी द्वारा एक रूहानी महफिल का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 4 जुलाई, शनिवार रात 10 बजे से गल्ला मंडी, आनंद पेट्रोल पंप के पास 'एक शाम शहीदाने कर्बला के नाम' शहीदी कव्वाली कार्यक्रम आयोजित होगा।

इस महफिल में मशहूर सूफियाना फनकार शवेज शरफत वारसी अपने कलाम पेश करेंगे। मोहर्रम कमेटी सालीचौका के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम में शहीदाने कर्बला की कुर्बानी, सब्र और ईमान का पैगाम कव्वाली के जरिए पेश किया जाएगा। कब्बाल शवेज शरफत वारसी अपने सूफियाना अंदाज में उन कलामों को पेश करेंगे जो दिलों को झकझोर देंगे।

उनके द्वारा पेश किए जाने वाले प्रमुख कलाम मे

तेरा सदक़ा अबु तालिब,
ताज वाले दिखा करबला,
मेरा ख्वाजा सदा नवाजे,
विनती सुनो सरकार मोरे वारिस

कलाम पेश किए जाएंगे । मोहर्रम कमेटी व कौमी एकता कमेटी सालीचौका के पदाधिकारियों ने क्षेत्र वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस रूहानी महफिल में शिरकत करें। कमेटी ने कहा कि कर्बला का पैगाम सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि इंसानियत, मज़लूम की मदद और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। कमेटी द्वारा कार्यक्रम की जोरशोर से तैयारियां की जा रही है ।कार्यक्रम स्थल गल्ला मंडी, आनंद पेट्रोल पंप के पास सजाया जाएगा। वहां बैठने, लाइट और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। कमेटी ने प्रशासन से कार्यक्रम मे सहयोग की मांग की

है। पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। आयोजन कमेटी ने 4 जुलाई शनिवार रात 10 बजे गल्ला मंडी सालीचौका मे आयोजित कब्बाली कार्यक्रम में सभी लोगो से शामिल होने की अपील की है ।

स्कूलों में दिलाई गई सायबर शपथ

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) गत दिवस सभी क्षेत्रीय स्कूलों में विद्यार्थियों क़ो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी निर्देशानुसार सायबर शपथ प्रार्थना सभा में दिलाई गई। शपथ में छात्र छात्राओं ने इंटरनेट का प्रयोग सुरक्षित और जिम्मेदारी से करने, स्वयं और अपने जानने वालों की व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और डाटा को सुरक्षित रखने, किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या संदेश पर भरोसा नहीं करने और दूसरों को भी सावधान करने, किसी परिचित व्यक्ति के साथ कोई साइबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर करने और इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देने, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने एवं सजग रहकर साइबर सुरक्षित समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सायबर अपराधों की रोकथाम एवं जनजागरूकता हेतु राज्य स्तरीय बृहद सायबर जागरूकता अभियान दिनांक-24 जून से 8 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में छात्र छात्राओं सायबर शपथ दिलाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

तेज बारिश से मंडी रखी किसानों की उपज बर्बाद, किसान हुए परेशान

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा I (राजेश नीरस) जवाहर कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल विक्रय के लिएय रखी हुई थी । बुधवार की दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। जिससे किसानों की उपज पूरी तरह पानी में भीगकर खराब हो गई । अचानक बारिस होते ही मंडी में चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया और किसान पत्नी तिरपाल से अपनी उपज को बचाने कोशिश करने लगे लेकिन बारिस बहुत तेज थी किसान की उपज पानी भीग गई । मंडी में विक्रय के लिए बड़ी मात्रा में किसानों की उपज आई थी। तेज बारिश ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। तिरपाल उड़ गए और फसलें पानी में भीग गईं।

किसानो का कहना है कि हमारी मेहनत उपज 10 मिनट की बारिश में पानी गीली हो गई ओर हमे काफी नुकसान हुआ है ।

खान क़ो सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) गत दिवस समीपी ग्राम खुरसीपार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक शेख जाफर खान की शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने श्री जाफ़र क़ो शाल,श्रीफल एवं उपहार देकर विदाई दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अंजू शुक्ला ने कहा कि श्री खान की सेवानिवृति से उनकी कमी विद्यालय क़ो खलेगी। ग्राम सरपंच मनोज दुबे ने कहा कि विद्यार्थियों क़ो बेहतर शिक्षा देने में श्री जाफर जी का योगदान सराहनीय रहा। अपने उदबोधन में शिक्षक शेख जाफर ने उन्हें मिले सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का आभार जताया। कार्यक्रम क़ो अन्य शिक्षकों ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक अवशेष उपाध्याय एवं अंत में आभार प्रदर्शन प्राचार्य पुरुषोत्तम पॉल ने किया। विदाई कार्यक्रम में रमाकांत शुक्ला, अरुण श्रीवास्तव,मकरंद कौरव,सेवानिवृत्त प्राचार्य अनूप शर्मा, प्रतुल इंदुरख्या, संदीप स्थापक, प्रसन्न दुबे, हरिराम कुशवाहा,रत्नेश विश्वकर्मा, प्रशांत पटैल, प्रदीप शर्मा, पुष्पलता ठाकुर,ज्योति चड़ार, सुनीता शर्मा, बबीता ठाकुर, सुमित ठाकुर, अवशेष उपाध्याय, संजय गुप्ता, अनिल मेहरा सहित सेवानिवृत्त शिक्षक शहनाज बानो खान, नरवर सराठे एवं रामकुमार तिनगुरिया सहित अन्य उपस्थित रहे

उप मुख्यमंत्री ने किया विन्ध्य विकास प्राधिकरण कार्यालय का भ्रमण

• साधना एक्सप्रेस, रीवा

रीवा | उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विंध्य विकास प्राधिकरण के नवीन कार्यालय डी-10 का भ्रमण किया।कार्यालय पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पंचुलाल प्रजापति, उपाध्यक्ष डॉ.अजय सिंह एवं विंध्य विकास प्राधिकरण के संयुक्त संचालक अनिल दुबे द्वारा स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित ।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490, प्रबंध संपादक आशीष नेमा मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा ।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698